वर्ष : 17 | अंक : 240 | मूल्य : 02 रुपया मात्र | पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

दिल्ली से प्रकाशित | शनिवार 20 जून 2026 | लोकतंत्र का स्तंभ

पीएम ओडिशा में 25,016 करोड़ की कोयला गैसीकरण परियोजना का करेंगे शिलान्यास

देश की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले-से-अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन परियोजना

एजेंसी। नई दिल्ली

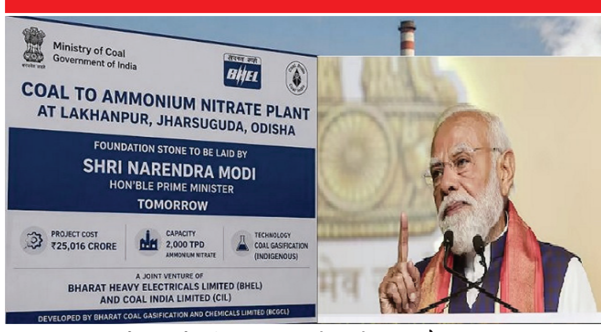

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए शनिवार (20 जून) को ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में 25,016 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। कोयला मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन पहल से कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 25 परियोजनाओं में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा मिलने और लगभग 50 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। लखनपुर परियोजना देश की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये परियोजना एमसीएल के कब्जे वाली लगभग 350 एकड़ भूमि पर बनेगी, जिसे आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है और शिलान्यास समारोह के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय ने इस तरह की परियोजनाओं के लिए कोयला युक्त भूमि के उपयोग को मंजूरी दी है और प्रोत्साहन योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रहा है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना का विकास भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के संयुक्त उद्यम भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) द्वारा किया जा रहा है। यह बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। इसके लिए अप्रैल में बीसीजीसीएल और सीआईएल की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के बीच भूमि पट्टे का समझौता हुआ था। सरकार ने कोयला गैसीकरण की अपार संभावनाओं को देखते हुए देशभर में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 46,000 करोड़ रुपये तक के कुल परिव्यय वाली प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजना भविष्य की कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगी और भारत के विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर और औद्योगिक शक्ति बनने के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और कोल इंडिया लिमिटेड विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है।

प्रधानमंत्री 20-21 जून को पश्चिम बंगाल दौरे पर, पीएम-किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 और 21 जून को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह हुगली जिले में पश्चिम बंग दिवस समारोह में भाग लेंगे, विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे, किसानों के लिए कई केंद्रीय कृषि योजनाओं की शुरुआत करेंगे तथा 21 जून को कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार 20 जून को प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वह रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पश्चिम बंगाल में 45 लाख से अधिक किसानों को 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत करेंगे। वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत राज्य के लगभग 50 लाख किसानों और 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 'एग्रीस्टैक', राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री दक्षिण 24 परगना जिले के फ्रेजरगंज में आधुनिकीकृत मत्स्य बंदरगाह तथा बीरभूम जिले के सैंथिया में नए आधुनिक मछली बाजार का उद्घाटन करेंगे।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

अमेरिका-ईरान युद्धः 7500 मौत, 162 लाख करोड़ का नुकसान फिर शांति विराम

मान्यता है इतिहास से सबक लिया जाता है। जो इतिहास से सबक लेते हैं, वे भविष्य में वह गलतियां नहीं करते हैं जो उनके पूर्वज कर चुके होते हैं। पर इतिहास से कोई सबक सीखता नहीं है, सभी को लगता है कि उनके पूर्वजों ने जो गलती की थी वह उनसे नहीं होगी। वह उनसे ज्यादा ताकतवर और समझदार हैं। इसलिए वह इतिहास की उन्हीं गलतियों को दोहराता है और एक बार फिर विनाश की ओर आगे बढ़ता है। विनाश के बाद विकास होने की गतिशीलता ही जन्म, मृत्यु और ब्रह्मांड को हमेशा क्रियाशील रखती है। यही कहा जा सकता है।

हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। अमेरिका और इजराइल यह मानकर चल रहे थे कि एक सप्ताह के अंदर इजराइल की सत्ता को पलट देंगे। वहां पर उनकी मर्जी से नया राज कायम हो जाएगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल की मनमर्जी से चलेगा। उन्होंने ईरान के सुप्रीमो आयतुल्लाह खामेनेई और उनके बड़े-बड़े नेताओं की हमले में हत्या कर दी। एक स्कूल में हमला कर 165 से ज्यादा मासूम बच्चियों की हत्या कर दी। इसके कारण जो ईरान आंतरिक असंतोष झेल रहा था, सुप्रीमो खामेनेई और बच्चियों की हत्या के बाद ईरान एकजुट हो गया और उसने अमेरिका और इजराइल से पिछले 47 वर्षों में उसके साथ जो अत्याचार हुए थे इसका बदला लेने के लिए डू एंड डाई की स्थिति में आ गए।

अमेरिका और इजराइल की दादागिरी को उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति और अपने जीवन को बचाने के लिए जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उससे सारी दुनिया हैरान है। अमेरिका, ईरान युद्ध में अभी तक 7500 से ज्यादा मोतें हो चुकी हैं। 110 दिन चले इस युद्ध में जमीन पर फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी है। सारी लड़ाई ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से लड़ी गई। इसमें लगभग 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले कई दशकों में जो विकास हुआ था वह सब विनाश में तब्दील हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आपको सुपर हीरो मानकर चल रहे थे इस 110 दिन की लड़ाई में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इससे जो उनकी अजेय होने साख बनी हुई थी वह समाप्त हो गई। इजराइल को जो नुकसान हुआ है, उसकी कल्पना कभी उसने नहीं की थी। गाजा में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह से मारा गया था, ऐसा नरसंहार दुनिया के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लगता है ईश्वर ने उनके अहंकार और स्वयं को ईश्वर मानने की जो गलती की थी उसका दंड दिया है। इस युद्ध में वैसे तो भारत का कोई लेना-देना नहीं था लेकिन जिस तरह से भारत ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया है। गाजा के मामले में चुप्पी साधे रखी।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

टेलीग्राम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका 22 तक प्रतिबंध बरकरार

नई दिल्ली। भारत में 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच दिन के अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और राष्ट्रीय हित में ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति उसके पास मौजूद है। टेलीग्राम की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध लगाने के पीछे पर्याप्त कारण मौजूद थे और आदेश की आपात प्रकृति को देखते हुए सरकार की कार्रवाई उचित थी। अदालत ने यह भी माना कि उपलब्ध सामग्री पर केंद्र सरकार ने विधिवत विचार किया था तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कोर्ट ने टेलीग्राम के उस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें आदेश की पूर्व सूचना न दिए जाने पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सरकार को आवश्यकता पड़ने पर पूरे प्लेटफॉर्म या ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश कानूनी रूप से वैध है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल कई बार आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक, साइबर ठगी और अन्य अवैध कार्यों के लिए किया जाता रहा है।

पासपोर्ट सेवा तेज, सुलभ और वास्तव में लोकतांत्रिक बन चुकी हैः विदेश मंत्री

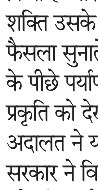

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शुक्रवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आज पासपोर्ट सेवा तेज, सुलभ और वास्तव में लोकतांत्रिक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि विश्वभर में भारतीय प्रतिभा की मांग और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सुगम और प्रभावी पासपोर्ट सेवाएं एक समृद्ध, वैश्विक रूप से जुड़े विकसित भारत की महत्वपूर्ण आधारशिला बनेंगी। जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति देश को 'विश्व बंधु' के रूप में स्थापित कर रही है। इसके कारण भारतीय पासपोर्ट को दुनिया भर में सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पासपोर्ट प्राप्त करना संघर्ष का विषय नहीं बल्कि नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में पासपोर्ट जारी करने का आंकड़ा 138 लाख से अधिक पहुंच गया है। यह भारतीय नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं और वैश्विक अवसरों की ओर उनके बढ़ते कदमों को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देशभर में केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे और वार्षिक पासपोर्ट जारी करने की संख्या 83 लाख थी। सरकार के व्यापक विस्तार अभियान के परिणामस्वरूप अब 544 कार्यरत केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 454 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल हैं। जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 ने विकसित भारत के लिए वैश्विक गतिशीलता को नई परिभाषा दी है।

पीएम मोदी की जी-7 शिखर सम्मेलन और स्वोवाकिया यात्रा ने वैश्विक मंच पर बढ़ाया भारत का कदः भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया जी-7 शिखर सम्मेलन और स्वोवाकिया यात्रा ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। पार्टी के अनुसार, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा थी और वहां प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में ही भारत को जी7 में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। ऐसा पहली बार 2003 में अटलजी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं कीं। भारत ने जी-7 देशों के समक्ष इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलेरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड (इंपैक्ट) का प्रस्ताव रखा, जिसमें सदस्य देशों ने रुचि दिखाई। यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जो विश्व स्तर पर उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार दुनिया के प्रमुख देशों का विश्वास अर्जित कर रहा है। साथ ही, फ्रांस द्वारा स्टेम शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 30 हजार भारतीय छात्रों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के फैसले को भी भारत-फ्रांस संबंधों की मजबूती का संकेत बताया गया।

तीन साल में अपराधी को सजा तक पहुंचाने वाली व्यवस्था बनाना लक्ष्य : अमित शाह

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को ऐसा प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिए, जो प्रत्येक नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति या सम्मान से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन होता है और वर्षों तक अपराधी को दंड नहीं मिलता, तो ऐसी व्यवस्था न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के सरदार वल्लभभाई पटेल सभागार में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन-2026 को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वर्ष 2019 में आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कानूनों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जांच प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाना तथा एफआईआर से लेकर अपराधी को दोषसिद्ध कराने तक की प्रक्रिया को तीन वर्ष के भीतर पूरा करना है। उन्होंने कहा कि देश वर्तमान में आपराधिक न्याय प्रणाली के परिवर्तन काल से गुजर रहा है। पहले थाना केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम माना जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी भूमिका अपराध नियंत्रण और जांच-पड़ताल तक विस्तारित हुई। अब आवश्यकता इस बात की है कि पूरी न्याय प्रणाली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का प्रभावी साधन बने। गृहमंत्री ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) की सराहना करते हुए कहा कि इसके जरिए कई जटिल मामलों को सुलझाने में सफलता मिली है, लेकिन इसका उपयोग अभी भी संभावित क्षमता का केवल 10 प्रतिशत ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनएएफआईएस केवल अपराधियों की पहचान करने का साधन नहीं है, बल्कि हर अपराध स्थल से प्राप्त फिंगरप्रिंट को प्रणाली में जोड़कर इसके डेटाबेस को समृद्ध करना भी उतना ही आवश्यक है। शाह ने कहा कि प्रशिक्षण केवल एप्लिकेशन के उपयोग तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्य तैयार करने, चार्जशीट दाखिल करने, अभियोजन और न्यायपालिका तक पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में होना चाहिए। जब फिंगरप्रिंट, डीएनए, चेहरे और टेलीफोन रिकॉर्ड जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हों, तो अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच, अभियोजन और दोषसिद्धि की पूरी श्रृंखला में तकनीक के सक्रिय उपयोग के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, ''लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।'' ओम बिरला ने कहा कि ईश्वर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर चलने, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में झलकती है। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, शक्ति और देश की सेवा में लंबी उम्र प्रदान करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि सच्चाई, निर्भीकता व साहस के पर्याय, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के नैतिक बल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा कि वर्षों से आपके साथ निकटता से काम करते हुए मैंने आपके भीतर एक ऐसे नेता को देखा है जो दृढ़ विश्वासों के साथ आगे बढ़ता है।

नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे चलाएगा छह विशेष ट्रेन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने 21 जून को पंजाब के विभिन्न शहरों के बीच छह विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियों के संचालन की घोषणा की है। इन विशेष ट्रेनों का संचालन अमृतसर, लुधियाना और फिरोजपुर कैंट के बीच किया जाएगा। उत्तर रेलवे के अनुसार, अमृतसर-लुधियाना-अमृतसर मार्ग पर रेलगाड़ी संख्या 04666/04665 स्पेशल का संचालन 21 जून को दो फेरों में किया जाएगा। यह ट्रेन अमृतसर, ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा और फिल्लौर होते हुए लुधियाना पहुंचेगी तथा वापसी में इसी मार्ग से अमृतसर लौटेगी। इसी प्रकार रेलगाड़ी संख्या 04667/04668 लुधियाना-अमृतसर-लुधियाना स्पेशल भी 21 जून को दो फेरों में चलाई जाएगी। यह ट्रेन लुधियाना से चलकर फिल्लौर, फगवाड़ा, जालंधर सिटी और ब्यास स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचेगी तथा वापसी में उसी मार्ग से लुधियाना लौटेगी। इसके अलावा फिरोजपुर कैंट-लुधियाना-फिरोजपुर कैंट मार्ग पर रेलगाड़ी संख्या 04670/04669 स्पेशल का संचालन भी दो फेरों में किया जाएगा।

नाइजर में एयरपोर्ट पर आतंकी हमला, 11 सैनिकों की मौत, 22 दहशतगर्द ढेर

एजेंसी। नियामी (नाइजर)

नाइजर की राजधानी नियामी में डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार तड़के आतंकवादी हमला हुआ है। एयरपोर्ट पर एक घंटे से ज्यादा समय तक धमाके और गोलीबारी होती रही। नाइजर गणराज्य की सैन्य सरकार की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि हमले में 11 सैनिक और 22 आतंकवादी मारे गए। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र 'प्रीमियर टाइम्स' नाइजीरिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में दो आम नागरिकों की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह गोलीबारी एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार के पास शुरू हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों को सारे परिसर को घेर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेना की घेराबंदी के बाद आतंकवादी इधर-उधर भागने लगे। नाइजर की सेना ने दहशतगर्दों का पीछा किया। भागते समय आतंकवादी हथियारों का जखीरा वहीं छोड़ गए थे। अभी तक किसी भी समूह ने एयरपोर्ट पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसी साल जनवरी में इसी एयरपोर्ट पर ऐसी ही एक घटना हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट इन द साहेल से जुड़े हथियारबंद आतंकवादियों ने मोर्टार और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कई तरफ से हमला किया था। उन्होंने नागरिक टर्मिनल और उससे सटे एयर बेस 101, दोनों को निशाना बनाया था। यह एयर बेस देश के सैन्य अभियानों के लिए एक अहम रणनीतिक केंद्र है। जनवरी के हमले में नाइजर की सेना के साथ रूसी अफ्रीका कॉर्प्स के लड़ाके भी थे।

अयोध्या राम मंदिरः सुरक्षा पर 11 माह में 10 करोड़ खर्च, फिर भी चोरी

एजेंसी। अयोध्या

रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के बीच अब सुरक्षा चूक और करोड़ों रुपये के खर्च के बावजूद कथित चोरी का मामला गरमा गया है। बीते 11 महीनों में मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद दान पेटियों में अनियमितता की शिकायत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में अब विशेष जांच दल की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका दायरा सिर्फ कथित चोरी तक सीमित न रहकर पूरे सिस्टम को खंगाल रहा है, जिससे कई बड़े नाम जांच के घेरे में आ गए हैं। 17 साल से एक ही जगह तैनात आरएमओ जांच के घेरे में इस जांच में जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर (आरएमओ) का है। यह वही अधिकारी है जिसके जिम्मे मंदिर परिसर की सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं की जिम्मेदारी है। सूत्र बताते हैं कि यह अधिकारी लगभग 17 वर्षों से मंदिर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इतने लंबे समय तक उसका तबादला न होना भी जांच के दायरे में है। एसआईटी सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, रिकॉर्डिंग सिस्टम, बैकअप व्यवस्था, डेटा संरक्षण और तकनीकी नियंत्रण से जुड़े तमाम पहलुओं पर बारीकी से जानकारी जुटा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक परिसरों में से एक, जहां सैकड़ों कैमरे और बहुस्तरीय सुरक्षा मौजूद है, वहां यह चूक आखिर कैसे संभव हुई? शुरुआत में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर केंद्रित रही यह जांच अब अपना दायरा बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी अब उन लोगों की भूमिका भी समझने की कोशिश कर रही है जो मंदिर की सुरक्षा, निगरानी और प्रवेश व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। इसमें तकनीकी स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि किसी भी बड़े परिसर में होने वाली गतिविधियों को समझने के लिए केवल घटना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है।

नड्डा ने विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर रोग उन्मूलन का लक्ष्य दोहराया

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर देशवासियों से स्वस्थ और अधिक समानतापूर्ण भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने की अपील की। उन्होंने आज एक्स पर पोस्ट कर विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 7.19 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है, जबकि 20.26 लाख से अधिक वाहकों (कैरियर्स) की पहचान की गई है। इसके अलावा 2.46 लाख लोगों में सिकल सेल रोग का निदान किया गया है तथा 4.82 करोड़ सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए हैं। ये उपलब्धियां विशेष रूप से आदिवासी आबादी और अन्य कमजोर समुदायों के बीच शुरुआती निदान, समय पर उपचार, आनुवंशिक परामर्श और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

पॉक्सो मामले में फरार आरोपित उत्तराखंड से गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली की वेलकम थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपित को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पर युवती को हथियार के बल पर धमका कर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लगातार पीछा करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार चार अप्रैल 2026 को 21 वर्षीय युवती ने वेलकम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में आरोपित ने पिस्तौल दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपित ने घटना का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण करता रहा। आरोप है कि वह युवती का ट्यूशन जाते समय पीछा करता था और उसके साथ-साथ परिवार के सदस्यों को भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम), 78, 351(3) और 126(2) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पता चला कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा-6 भी जोड़ दी गई। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। तकनीकी निगरानी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी हासिल किए थे और उसे घोषित अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। एसीपी भजनपुरा सहदेव कुमार राणा की निगरानी और थाना प्रभारी रूपेश कुमार खत्री के नेतृत्व में एएसआई बिजेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल हरेंद्र कुमार, कुलदीप और ललित, कांस्टेबल लोकेश तथा महिला कांस्टेबल शिवानी की टीम ने लगातार प्रयास किए। पुलिस को मिली विशेष सूचना के आधार पर टीम ने उत्तराखंड के भगवानपुर में छापेमारी कर 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वेलकम इलाके का रहने वाला है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित पहले भी गैर इरादतन हत्या और जुआ अधिनियम से जुड़े मामलों में संलिप्त रह चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

हिमालय क्षेत्र में बनेगा देश का नया जलवायु निगरानी केंद्र

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। हिमालय क्षेत्र में देश का नया जलवायु निगरानी केंद्र बनने जा रहा है। यह कदम जलवायु अनुसंधान को मजबूती प्रदान करेगा। इस संबंध में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एआरआईईएस) नैनीताल के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 50 वर्षों से अधिक अवधि के लिए मान्य होगी।समझौते के तहत उत्तराखंड के देवस्थल वेधशाला में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क (बीसीओएन) के अंतर्गत दीर्घकालिक जलवायु अवलोकन केंद्र स्थापित किया जाएगा।विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी जानकारी के अनुसार यह केंद्र हिमालयी क्षेत्र में मौसम, ग्रीनहाउस गैसों, वायुमंडलीय प्रदूषकों और मिट्टी की नमी जैसे महत्वपूर्ण मानकों की निगरानी करेगा।वैज्ञानिकों के अनुसार, देवस्थल का स्वच्छ और ऊंचाई वाला वातावरण जलवायु परिवर्तन से जुड़े अध्ययनों के लिए बेहद उपयुक्त है। यहां से प्राप्त आंकड़े हिमालयी क्षेत्र में जलवायु प्रक्रियाओं को समझने और प्रदूषण के प्रभावों का आकलन करने में मदद करेंगे।बीसीओएन परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर में उच्च-गुणवत्ता वाला जलवायु डेटा तैयार करना और जलवायु परिवर्तन पर शोध को बढ़ावा देना है। नेटवर्क से प्राप्त आंकड़े भारत के जलवायु मॉडल और भविष्य के मौसम एवं जलवायु पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने में भी सहायक होंगे। यह पहल भारत को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और वैज्ञानिक आधार पर नीति निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

एनएचआरसी का नाबालिग को जेल में रखने को लेकर उप्र के डीजीपी व अन्य को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के कासना जेल में एक नाबालिग को वयस्क कैदी की तरह हिरासत में रखने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल प्रशासन, सुधार सेवा महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।मीडिया की रिपोर्ट में अप्रैल महीने में गौतमबुद्ध नगर में मजदूरों ने वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तारी के बाद किशोर को कासना जेल भेज दिया गया। बाद में हुए मेडिकल टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह नाबालिग है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी उसे किशोर सुधारगृह में स्थानांतरित करने में प्रशासन को 6 दिन का समय लग गया।पीड़ित युवक को जमानत मिल चुकी है लेकिन वह आज भी सुधारगृह में ही बंद है। उसका परिवार बेहद गरीब है और अदालत द्वारा तय की गई जमानत राशि का इंतजाम करने में असमर्थ है। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और डरा-धमकाकर जबरन कुछ खाली दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। एनएचआरसी अब इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रहा है।

दिल्ली सरकार ने शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था को किया अधिसूचित

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब सरकार सर्दियों की शुरुआत से कई महीने पहले ही यह स्पष्ट कर रही है कि नवंबर से फरवरी के दौरान प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, किन व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है और विभिन्न क्षेत्रों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी। इससे नागरिकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों को अग्रिम योजना बनाने और आवश्यक तैयारियां करने का पर्याप्त समय मिलेगा।मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से नवंबर से फरवरी के बीच वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती रही है और एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) अक्सर 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है। यह हालात हर वर्ष पैदा हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया पर निर्भर रहने के बजाय अग्रिम तैयारी, समयबद्ध हस्तक्षेप और बेहतर समन्वय पर आधारित रणनीति अपनाई है। यह फ्रेमवर्क पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के पूरक के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विभाग और एजेंसियां सर्दियों के महीनों में निरंतर तैयार रहें और प्रदूषण नियंत्रण उपाय प्रतिकूल परिस्थितियों के आने से पहले ही लागू किए जा सकें न कि केवल ग्रैप लागू होने के बाद।मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिसूचित व्यवस्था के तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) होगा। इसके अतिरिक्त 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-VI वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को इस व्यवस्था से छूट दी जाएगी। सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता सुधारने और निजी वाहनों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के उद्देश्य से 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने कह कि यातायात दबाव कम करने, आवागमन को अधिक व्यवस्थित बनाने और प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए चरणबद्ध कार्यालय समय की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत सरकारी व निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे और शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कार्य कर सकेंगे। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट रहेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियां शहरी विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए परियोजना संचालकों, ठेकेदारों और नागरिकों को अपनी गतिविधियों की योजना पहले से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि अत्यधिक प्रदूषण वाले समय में अतिरिक्त प्रदूषण भार न बढ़े। इसी के मद्देनजर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के अनुरूप संचालित करना होगा। विशेष रूप से 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच, जब प्रदूषण का स्तर अधिक रहने की संभावना होती है, तब जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के हित में निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं को इससे छूट दी जा सकती है। उच्च प्रदूषण अवधि के दौरान निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को भी विनियमित (रेगुलेट) किया जा सकता है। साथ ही, बड़े वाणिज्यिक ऊंचे भवनों और प्रमुख निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सप्रेशन सिस्टम और अन्य धूल नियंत्रण उपायों की स्थापना एवं संचालन अनिवार्य होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए खुले में कचरा, पत्तियां या अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। सभी आरडब्ल्यूए, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और एजेंसियों को अपने क्षेत्रों में खुले में जलाने की गतिविधि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। विशेष रूप से सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा सर्दियों में आग जलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वैकल्पिक हीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि खुले में जलाने की घटनाओं की पहचान और रोकथाम के लिए फील्ड सर्विलांस और ड्रोन आधारित निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सहित लागू कानूनों के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अधिसूचित दिशा-निर्देश प्रत्येक वर्ष सामान्यतः 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे और ग्रैप के साथ समानांतर रूप से लागू होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए सरकार, नागरिकों, आरडब्ल्यूए, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों की साझी भागीदारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इन उपायों की अग्रिम सूचना दी जा रही है ताकि सभी संबंधित पक्ष समय रहते आवश्यक तैयारियां कर सकें और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा को लेकर आयोग ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक एडवाइजरी जारी की है। शुक्रवार को आयोग की तरफ से जारी एडवाइजरी में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम (पोश एक्ट), 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश की गई है। एडवाइजरी में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों में वार्षिक पोश ऑडिट अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है।आयोग की तरफ से जारी परामर्श में राज्यों को पोश मॉनिटरिंग सेल या डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित कर कानून के अनुपालन की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। आयोग ने सभी

सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और निजी प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही, असंगठित क्षेत्र, घरेलू कामगारों और छोटे प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए स्थानीय समितियों को मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है।एडवाइजरी में ब्लॉक, तहसील और नगर स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, पोश कानून के प्रति जागरूकता अभियान, समिति सदस्यों के प्रशिक्षण तथा शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ना और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी शामिल हैं। आयोग ने केंद्र सरकार के शी बॉक्स पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने तथा शिकायत प्रक्रिया और समिति संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने पर भी बल दिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए।इन उपायों से देशभर में महिलाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और लैंगिक संवेदनशील कार्यस्थल संस्कृति विकसित होगी तथा कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

कांग्रेस ने कहा- मोदी सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर उसे व्यापार बनाया

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः कांग्रेस ने देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस नेता डॉ. कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर इसे व्यापार बना दिया है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और एनएसयूआई प्रभारी डॉ. कन्हैया कुमार ने नीट परीक्षा में लगातार हो रही गड़बड़ियों का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग दोहराई। साथ ही कहा कि

पेपर लीक के सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सक्षम संस्थान स्थापित किया जाए।

ऑपरेशन विश्वासः 15 दिन में 168 खोए मोबाइल बरामद, बिहार-उप्र समेत कई राज्यों से तलाशकर 88 फोन मालिकों को लौटाए

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। मध्य जिला पुलिस ने तकनीक आधारित पुलिसिंग और अंतरराज्यीय समन्वय का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत महज 15 दिनों में 168 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन में से 88 हैंडसेट को अनब्लॉक कर स्वामित्व सत्यापन के बाद उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया।पुलिस का कहना है कि इस विशेष अभियान ने न केवल लोगों को उनके महंगे मोबाइल वापस दिलाए, बल्कि उनमें मौजूद महत्वपूर्ण निजी और पेशेवर डेटा को भी सुरक्षित लौटाने में अहम भूमिका निभाई है।पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार यह अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया। इसका उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फोन को तकनीकी सहायता और समन्वित पुलिसिंग के जरिए ट्रेस कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाना था। ऑपरेशन विश्वास के तहत केंद्रीय जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और सभी थानों के नामित नोडल अधिकारियों ने संयुक्त रूप से काम किया। टीमों ने खोए हुए मोबाइल फोन से संबंधित शिकायतों का विश्लेषण किया और प्रत्येक मामले में लगातार फॉलोअप किया।मोबाइल फोन की बरामदगी में तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल ट्रैकिंग ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने उपलब्ध तकनीकी संसाधनों और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से मोबाइल फोन की लोकेशन, उनकी गतिविधियों और वर्तमान उपयोगकर्ताओं की पहचान की। जांच के दौरान हर सुराग की बारीकी से पड़ताल की गई।पुलिस के अनुसार कई मोबाइल फोन एक से अधिक लोगों के हाथों में पहुंच चुके थे और दिल्ली से बाहर विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसके बावजूद पुलिस टीमों ने लगातार तकनीकी निगरानी और स्थानीय पुलिस इकाइयों के सहयोग से मोबाइल फोन का पता लगाया।जांच में सामने आया कि खोए हुए मोबाइल फोन बिहार, उप्र और देश के अन्य हिस्सों में पहुंच चुके थे। ऐसे में केंद्रीय जिला पुलिस ने संबंधित राज्यों की स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बरामदगी अभियान चलाया। अंतरराज्यीय सहयोग और लगातार फील्ड वर्क के चलते 168 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता मिली।पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन का स्वामित्व सत्यापित किया गया। आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 88 मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक अनब्लॉक किया गया और उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि कई मोबाइल फोन सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर ब्लॉक किए गए थे, जिन्हें बरामदगी के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा सक्रिय किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइल फोन में केवल महंगे उपकरण ही नहीं, बल्कि लोगों का महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और पेशेवर डेटा भी सुरक्षित था। इनमें बैंकिंग एप्लीकेशन, वित्तीय जानकारी, व्यावसायिक दस्तावेज, व्यक्तिगत तस्वीरें, संपर्क सूची और परिवार से जुड़ी अनमोल यादें शामिल थीं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस टीमों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि फोन के साथ उनका महत्वपूर्ण डेटा भी सुरक्षित लौट आया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

एनडीएमसी के आठ प्रमुख स्थलों पर आठ योग संस्थाओं की सहभागिता से आयोजित होगा योग दिवस

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु एनडीएमसी क्षेत्र के आठ प्रतिष्ठित स्थलों पर व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" निर्धारित किया गया।बढ़ती जनभागीदारी एवं व्यापक जनसंपर्क गतिविधियों के बीच 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के भव्य समारोह की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ अंतिम चरण में हैं। विशेष रूप से कर्तव्य पथ, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन एवं शांति पथ लॉन जैसे प्रमुख स्थलों पर बड़ी संख्या में सहभागिता की संभावना है।इस आयोजन में 5,000 से अधिक योग साधकों, स्थानीय निवासियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), विद्यार्थियों, अधिकारियों तथा आगंतुकों के भाग लेने की संभावना है, जिससे यह राजधानी के हृदयस्थल में आयोजित सबसे बड़े समन्वित जन-स्वास्थ्य एवं जन-कल्याण

अभियानों में से एक होगा।एनडीएमसी ने अनुसार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन आठ स्थलों पर किया जाएगा । ये स्थल है - शांति पथ लॉन, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग (आईएएस आवास), संजय झील (लक्ष्मी बाई नगर), पंडारा पार्क तथा पालिका पार्क (कनॉट प्लेस)।इन स्थलों पर योग सत्रों एवं प्रदर्शनों के संचालन हेतु प्रतिष्ठित योग संस्थाएं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योग समिति, गायत्री परिवार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, ईशा योग केंद्र, द योग गुरु इंस्टीट्यूट, मोक्षायतन योग संस्थान तथा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एनडीएमसी के साथ सहभागिता करेंगी। कार्यक्रम के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एनडीएमसी ने विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों पर आधारित एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। जनभागीदारी पर विशेष जोर के लिए एनडीएमसी ने सभी नोडल अधिकारियों को स्थानीय निवासियों, आरडब्ल्यूए, संस्थानों एवं सामुदायिक संगठनों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करने तथा अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही योग के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम एवं पूर्व-आयोजन योग गतिविधियां भी एनडीएमसी क्षेत्र में आयोजित की जा रही हैं।अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के अंतर्गत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा 19 एवं 20 जून को राजधानी के दो प्रमुख हरित स्थलों—तालकटोरा गार्डन एवं लोधी गार्डन में विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं। ये निःशुल्क सामुदायिक सत्र प्रशिक्षित विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में योग अभ्यास उपलब्ध कराते हैं तथा सभी आयु वर्गों के लोगों में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व को बढ़ावा देते हुए सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।इसके अतिरिक्त, एनडीएमसी की आयुष इकाइयां विभिन्न स्थलों पर योग सत्र, जागरूकता कार्यक्रम तथा कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) अभ्यास आयोजित कर रही हैं। स्वास्थ्य एवं सतत जीवनशैली के प्रति एनडीएमसी की प्रतिबद्धता , अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वस्थ जीवनशैली, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय जागरूकता एवं सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एनडीएमसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन पहलों के माध्यम से एनडीएमसी नागरिकों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना चाहती है, जिससे शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिल सके। एनडीएमसी सभी निवासियों, नागरिकों, विद्यार्थियों एवं आगंतुकों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में शामिल होकर स्वास्थ्य, सद्भाव एवं कल्याण के इस वैश्विक जनआंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की।

दिल्ली के पहले महिला पुलिस स्टेशन का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस कदम का मकसद महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके ख़िलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के तरीके को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और सशक्त महिला ही प्रगतिशील समाज की नींव होती है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ लक्ष्मी सिंह मौजूद रहीं।उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन से प्रेरित होकर कि 'नारी शक्ति' ही राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला है, यह महत्वपूर्ण संस्थान महिलाओं को बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज कराने, न्याय पाने और सहायता प्राप्त

करने के लिए एक सहयोगी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की महिला-सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख पहलों, जैसे 'पिंक बूथ' और 'सशक्ति' अभियान की भी समीक्षा की। पुलिस बल को राजधानी में ऐसे और केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि महिला-अनुकूल पुलिसिंग और तत्परता से कानून लागू करने की दिशा में एक नया मानक स्थापित किया जा सके। उपराज्यपाल ने कहा कि एक सुरक्षित और सशक्त महिला ही प्रगतिशील समाज की नींव होती है। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में काम करते रहेंगे। अगर हम कोई अपराध होते या अपनी माताओं, बहनों और परिवार के साथ अन्याय होते देखें तो जरूर आवाज उठाएं या पुलिस को सूचित करें। यह एक ऐसा सीधा जरिया है जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध से सीधे निपटेगा।

संक्षिप्त समाचार

एसआईटी जांच कर रही, दूध का दूध-पानी का पानी होगाः मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान , अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रकरण पर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम के अस्तित्व को नकारने वाले, रामभक्तों पर लाठी-गोली चलाने वाले उपदेश दे रहे हैं। अयोध्या को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या के बारे में समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली, उसके बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर हमने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट आने तक ऐसी कोई बयानबाजी न हो, जो रामभक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। यदि किसी के पास डाक्यूमेंट्री प्रूफ हो तो एसआईटी को उपलब्ध करा दें। सीएम ने रामभक्तों से विनम्र अपील की कि प्रभु राम ने हमें मर्यादित रहने का आचरण दिया है, इसलिए मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने प्रभु के स्थान के लिए मर्यादित रहते हुए 500 वर्षों तक संघर्ष किया है, 15 दिन और इंतजार कर लें। अगर कोई अपराधी है तो यह सुनिश्चित है कि वह कोई भी हो, बचेगा नहीं।

पैसे दे किसान तभी बनेगी STW 13 नंबर की लाइन

लोकतंत्र की शान , मुरवल/बांदा। एक महीना पूरा होने को है लेकिन अभी तक मुरवल पावर हाउस से रगौली फीडर अंतर्गत एसटीडब्ल्यू तेरह नंबर की मेन लाइन लाइन मैन और अधिकारियों की उदासीनता के चलते लावारिश अवस्था में पड़ी है, एक तो आग उबलता मौसम और खराब लाइन और समय से बारिश का अभाव तो वहीं उदासीनता के चलते किसानों की अरमानों में पानी फेर रहा है बिजली विभाग। विगत हो कि मुरवल पॉवर हाउस अंतर्गत रगौली फीडर एसटीडब्ल्यू तेरह नंबर सरकारी ट्यूब बेल की मेन लाइन पिछले महीने आई तेज आधी की वजह से एक पोल का तार टूट गया था जिसके कारण यह लाइन आज भी अचेत अवस्था में उसी तरह बंद पड़ी हुई है किसानों ने कई बार सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के इसकी जानकारी भी दी बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए है। किसानों ने बताया कि यह लाइन एक सरकारी ट्यूब बेल सहित बारह प्राइवेट ट्यूब बेल को संचालित करती है लेकिन इस लाइन को दुरुस्त करने के लिए कई बार लाइनमैनो को अवगत कराया गया लेकिन पैसे के अभाव में कोई सुनाई नहीं हो रही, वही आरोप है कि लाइन मैन राजू पाल और संविदा कर्मचारी अनूप तिवारी उसी प्राइवेट लाइन में जाकर काम करते है जिसमें उनको गांधी जी के दर्शन होते है जिसकी शिकायतx किसानों ने कई बार सम्बंधित विभाग के जेई अनिल कुमार से भी की बावजूद इसके उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की इसके चलते लाइनमैनो के भाव सातवें आसमान में पहुंच गए और वह खुलेआम लाइन सही करने के नाम पर खुले आम रिश्वत खोरी का डिढौरा पीट रहे है, पैसे दो तभी काम होगा अन्यथा पड़ी रहे लाइन, अधिकारियों को ज्यादा पड़ी हो तो आकर सही करे हम नहीं करेंगे।

इस बाबत जब हमने संबधित जेई अनिल कुमार से जानकारी लेने के लिए दूरभाष के जरिए संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका नंबर बंद पाया गया वही एसडीओ बबेरू ने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा जिससे अब साफ हो गया है कि बिजली विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद में मस्त है और किसानो की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है।

चित्रकूट धाम जल संस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा

10 साल से ठप्प पड़े बोरवेल के नाम पर उठाई जा रही सैलरी

लोकतंत्र की शान , नरैनी/बांदा। नरैनी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कटरा कालिंजर से भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में पिछले 10 वर्षों से सरकारी जल आपूर्ति पूरी तरह ठप्प पड़ी है, लेकिन कागजों पर काम दिखाकर हर महीने सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कटरा कालिंजर में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चित्रकूट धाम जल संस्थान द्वारा गाँव के एक कुएं में बोरिंग कराई गई थी। इसके साथ ही वहाँ एक कमरा और जल संसाधन के अन्य आवश्यक उपकरण भी लगाए गए थे ताकि पाइपलाइन के माध्यम से पूरे गाँव को पानी मिल सके। स्थानीय निवासियों मनीष, आशीष, नीलांशु, अनिल, मुकेश का कहना है कि यह पूरी व्यवस्था पिछले करीब 10 सालों से बंद पड़ी है और गाँव में बूंद-बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जल आपूर्ति ठप्प होने के बावजूद विभाग के संबंधित जूनियर इंजीनियर की कथित मिलीभगत से बड़ा खेल चल रहा है। गाँव के ही निवासी शैलेंद्र कुमार और शोभित बिना कोई काम किए, कथित तौर पर जल संस्थान से 4,200 प्रति माह की मानदेय/सैलरी उठा रहे हैं। जब 10 साल से पानी की एक बूंद सप्लाई नहीं हुई, तो इन कर्मचारियों को किस बात का भुगतान किया जा रहा है? यह सीधे तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार है। ग्रामीणों का कहना है कि इस धांधली और फर्जीवाड़े के संबंध में पहले भी कई बार संबंधित उच्चाधिकारियों और विभाग को लिखित शिकायतें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों की इस अनदेखी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि बांदा जिला प्रशासन और जल संस्थान के आला अधिकारी इस गंभीर मामले का संज्ञान लेकर कब तक दोषियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर ग्रामीण यूँ ही पानी और न्याय के लिए भटकते रहेंगे।

ओबीसी युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मुफ्त में सीखें ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर कोर्स

लोकतंत्र की शान , बाँदा। उत्तर प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जनपद के अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया गया है। विभाग द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभिषेक चौधरी ने जनपद के सभी पात्र ओबीसी युवाओं से अपील की है कि वे समय रहते इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर हार्डकॉपी कार्यालय में जमा कर दें। अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

गंगेश्वरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिवस

लोकतंत्र की शान/ सतीश चंद्र राणा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष शमशाद सैफी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन, जनहित के मुद्दों पर चर्चा की । उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार किसानों, युवाओं, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दों पर मिलकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। इस मोके पर खुर्शीद, विकास कुमार, साबिर सेठ, जावेद सैफी, जमील अहमद, विक्रम सिंह, लोकेश कुमार, सत्तर सैफी, युसूफ सैफी, फारूक, विनोद कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण के साथ हुआ। आयोजन में कार्यकर्ताओं के उत्साह और सहभागिता ने संगठन की एकजुटता का संदेश दिया।

सीएम योगी ने रामलला व हनुमानगढ़ी में झुकाया शीश

लोकतंत्र की शान

» जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का किया स्वागत
» मुख्यमंत्री ने संतों से की मुलाकात, पूछा कुशलक्षेम

अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रामनगरी पहुंचे। उन्होंने यहां विकास की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में संकट मोचन के चरणों में हाजिरी लगाई। यहां उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्रीरामलला के चरणों में भी प्रणाम निवेदित किया। सीएम योगी रामकथा पार्क स्थित हैलीपेड पर पहुंचे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। रामकथा पार्क से सीएम योगी सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां रामभक्त संकटमोचन हनुमान के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रदेश के कल्याण की कामना की। सीएम ने दर्शन-पूजन के उपरांत निकलते समय आमजन का अभिवादन भी स्वीकार किया।

जिलाधिकारी, रामपुर एवं पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा आगामी नीट (NEET) परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के हेतु की गयी गोष्ठी

लोकतंत्र की शान/ मंडल प्रभारी
अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर /उत्तर प्रदेश/ रामपुर के विकास भवन सभागार,में आगामी नीट (NEET) परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी, रामपुर एवं पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई । परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, परीक्षा केन्द्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों की सुगम आवाजाही तथा परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई । संबंधित प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केन्द्रों पर सतर्कता बनाए रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे परीक्षा निष्पक्ष एवं व्यवधानरहित वातावरण में सम्पन्न हो सके ।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भीम आर्मी का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

लोकतंत्र की शान / सतीश चंद राणा

सोशल मीडिया पर अनुसूचित समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और जातिसूचक टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर के ब्लॉक तिराहे से हसनपुर कोतवाली तक पैदल मार्च निकालकर रोष व्यक्त किया और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण के दौरान कुछ लोगों द्वारा अनुसूचित समाज एवं बहुजन महापुरुषों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। हसनपुर कोतवाली पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना रुक सकै । इस मोके पर कुलदीप सम्राट जिला अध्यक्ष राजू सागर आकाश सागर विपिन सम्राट मोनू जाटव उमेश कुमार सोनू जाटव आदि संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामपुर जिलाधिकारी अजय द्विवेदी द्वारा सेवा सुशासन संस्कार एवं सम्मान सर्टिफिकेट वितरण किए गए

लोकतंत्र की शान/ मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर/ उत्तर प्रदेश/ रामपुर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेवा सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, संस्कार एवं सम्मान के साथ 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार , पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी , राज्य महिला आयोग सदस्य सुनीता सिंह सैनी की उपस्थिति में विकास भवन परिसर में प्राकृतिक एवं प्रगतिशील खेती कार्यशाला तथा कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय कृषक गोष्ठी-2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कृषकों से उन्नत एवं प्राकृतिक खेती पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सहायता तथा सिंचाई के लिए अनुदानित दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जीवामृत के निर्माण का लाइव प्रदर्शन किया तथा किसानों को इसके प्रयोग की विधि से अवगत कराया। रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती अपनाने के लाभों पर प्रकाश डाला। उर्वरकों की बुकिंग की नई व्यवस्था तथा "फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल" ऐप के माध्यम से उर्वरक बुकिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी और किसानों को डिजिटल माध्यमों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों पर विस्तार से जानकारी देते हुए जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, आच्छादन एवं वाफसा आधारित तकनीकों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत घटती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है।

हसनपुर सीएचसी में योग शिविर आयोजित किया गया

लोकतंत्र की शान / सतीश चंद्र राणा

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी हसनपुर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने योगाभ्यास कर योग के महत्व को समझा। इस अवसर पर सीएचसी प्रभारी डॉ. ध्रुवेंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को योग के लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा अनेक बीमारियों से बचाव होता है। उन्होंने बताया कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोग जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया तथा नियमित योग करने का संकल्प लिया। इस मोके पर डॉ. ध्रुवेंद्र सिंह एम.के. जोशी, साहिल सिंह, आरती शर्मा, मनु सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया ।

सरकड़ी नहर में हादसा, 33 वर्षीय युवक की मौत

घंटों की तलाश के बाद मिला शव

लोकतंत्र की शान

बिजनौर। स्योहारा थाना क्षेत्र के सरकड़ी स्थित सरकारी नहर में डूबे युवक का शव करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय गोताखोरों और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। संयुक्त प्रयासों से चलाए गए सर्च अभियान के बाद युवक का शव नहर से बाहर निकाला गया। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सदाफल पुल के पास एक युवक नहर में डूब गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई। ग्रामीणों ने बताया कि नहर में डूबने वाला युवक मनजीत पुत्र मांगू सिंह निवासी रामपुर दुल्ली उर्फ झिल्ला है, जो पेशे से ई-रिक्शा चालक था। घटनास्थल के पास उसकी ई-रिक्शा खड़ी मिली। ई-रिक्शा में उसकी शर्ट और ट्राउजर रखे हुए थे, जबकि चप्पल भी वहीं पड़े मिले। इससे आशंका जताई गई कि युवक नहर में नहाने के लिए उतरा होगा और किसी कारणवश गहरे पानी में चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश अभियान शुरू कराया। इसी दौरान अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और खोजबीन अभियान में सहयोग किया। करीब ढाई घंटे तक चले संयुक्त सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव नहर से बरामद कर लिया गया। मामले में एक रहस्यमय पहलू भी सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के वक्त घटनास्थल के पास तीन ए रिक्शा खड़ी थी। लेकिन वहां बाद में सिर्फ एक ही ई रिक्शा वहां मौजूद मिली जो मृतक की थी। सवाल यह है कि आखिर वे दो ई रिक्शा कहां गई। यह भी जांच का विषय है। बताया गया कि लगभग 33 वर्षीय मनजीत विवाहित था और उसका ढाई वर्ष का एक पुत्र भी है। शव मिलने की सूचना के बाद परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बरेली को मिलेगी विकास की नई उड़ानः BDA उपाध्यक्ष IAS सौम्या पांडेय ने संभाला मोर्चा, इंडस्ट्रियल टाउनशिप से महादेवपुरम तक परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) मुख्यमंत्री के संभावित बरेली दौरे से पहले शहर के विकास कार्यों में तेजी दिखाई देने लगी है। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की उपाध्यक्ष IAS सौम्या पांडेय ने खुद मैदान में उतरकर विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों, अभियंताओं और ठेकेदारों के साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने इंडस्ट्रियल टाउनशिप, महादेवपुरम आवासीय योजना, साइंस पार्क, बॉक्स विलेज, मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल, रुद्र वनम पार्क, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना, ओवरहेड वाटर टैंक, नाले निर्माण और निर्माणाधीन एसटीपी परियोजना सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी विकास और रोजगार का नया केंद्र-निरीक्षण की शुरुआत मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना इंडस्ट्रियल टाउनशिप से हुई। समीक्षा के दौरान भूमि अर्जन की प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी बाधाओं का तत्काल समाधान कर परियोजना को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की दिशा में ठोस योजना तैयार की जाए। इसके लिए मानचित्र में आवश्यक परिवर्तन और कनेक्टिविटी के विकल्पों पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि इस कनेक्टिविटी से भविष्य में उद्योगों का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को जल्द मिलेगा कब्जा-प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जा रहे आवासों का भी निरीक्षण किया गया। समीक्षा में सामने आया कि कई स्थानों पर कार्यों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर आवंटन और कब्जा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवासीय परिसर को अधिक सुविधाजनक, आकर्षक और बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए निर्माण एजेंसियों को आवश्यक सुधार करने को कहा गया।

संक्षिप्त समाचार

डिवाइडर से टकराया ऑटो, 11 यात्री घायल, हाजीपुर में नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट के बाद 4 की हालत गंभीर

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच 22 पर सदर थाना क्षेत्र के रामाशीष चौक ओवरब्रिज पर एक अनियंत्रित टेंपो डिवाइडर से टकरा गया। इस दुर्घटना में टेंपो में सवार 11 यात्री घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया। चार गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज जारी है, जबकि सात अन्य को मामूली चोटें आई हैं। घायलों में भगवानपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर पट्टी गांव निवासी 43 वर्षीय अमित सिंह, जुरवनपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव निवासी 30 वर्षीय विकास राय, और भगवानपुर के सतपुरा गांव निवासी 28 वर्षीय अंजली कुमारी शामिल हैं। अंजली के पति शिवनाथ प्रसाद गुप्ता भी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। बताया गया है कि टेंपो मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की ओर आ रहा था। रामाशीष चौक ओवरब्रिज पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह डिवाइडर से टकरा गया। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टेंपो के नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

महात्मा गांधी सेतु पर ट्रक-पिकअप की टक्कर, चालक केबिन में फंसा, पश्चिमी लेन एक घंटे तक जाम

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। महात्मा गांधी सेतु की पश्चिमी लेन पर ट्रक और लकड़ी से लदी पिकअप के बीच टक्कर हो गई। यह हादसा पाया नंबर 18 के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसका चालक केबिन में फंस गया। इस घटना के कारण पुल पर लंबा जाम लग गया। पुलिस के अनुसार, पटना से हाजीपुर की ओर जा रहे एक ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार लकड़ी लदी पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप पर लदी लकड़ी सड़क पर बिखर गई, जिससे यातायात बाधित हुआ। राहगीरों ने तत्काल गंगा ब्रिज थाने की पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गंगा ब्रिज थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद पिकअप चालक को क्षतिग्रस्त केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला। उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को सड़क से हटाकर थाने पहुंचाया। इस दुर्घटना के कारण पश्चिमी लेन पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुल पर करीब तीन घंटे से अधिक समय तक भीषण जाम लगा रहा। पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने के बाद ही पश्चिमी लेन पर यातायात सुचारू रूप से बहाल हो सका। गंगा ब्रिज थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि चलती ट्रक में पिकअप द्वारा टक्कर मारने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पिकअप को थाने पर लाया। थानाध्यक्ष के अनुसार, इस दौरान लगभग एक घंटे तक पश्चिमी लेन पर यातायात बाधित रहा।

सड़क हादसे में चाचा-भतीजा घायल, देसरी के गाजीपुर में ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। हाजीपुर में एक सड़क हादसे में चाचा-भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना करीब 12 बजे देसरी थाना क्षेत्र के गाजीपुर में हुई। उनकी बाइक एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गई थी। घायलों की पहचान 22 वर्षीय आकाश कुमार (पिता- उमेश राय) और उनके चाचा वीरेंद्र राय (पिता- स्वर्गीय जवाहर राय) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहले गाजीपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हाजीपुर सदर अस्पताल में चिकित्सक डॉ. राकेश कुमार की देखरेख में आकाश कुमार का इलाज जारी है। वहीं, शिक्षक वीरेंद्र राय की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए पटना PMCH रेफर किया गया है। परिजनों के अनुसार, वीरेंद्र राय बाइक चला रहे थे और आकाश उनके पीछे बैठे थे। वे महुआ में एक रिश्तेदार के घर से बिदुपुर के कल्याणपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे। वीरेंद्र राय एक सरकारी शिक्षक हैं और बिदुपुर क्षेत्र के एक बुनियादी विद्यालय में कार्यरत हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार होने लगा। स्थानीय लोगों ने पीछा कर जंदाहा थाना क्षेत्र में ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि, चालक ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर जंदाहा थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। जंदाहा थाना प्रभारी अनामिका कुमारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद भाग रहे ट्रक को जब्त कर थाने लाया गया है। घटना की सूचना संबंधित थाने को दे दी गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बीपीएससी शिक्षिका की नौकरी पर संकट, शादीशुदा होते हुए खुद को बताया था अनमैरिड

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की एक BPSC शिक्षिका की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षिका के ससुरालवालों की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की है। आरोप लगाया है कि शिक्षिका ने नियुक्ति के दौरान गलत जानकारी और दस्तावेज दी है। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले प्रवीण कुमार विश्वकर्मा की शादी 2 दिसंबर 2022 को बिंदु के साथ हुई थी। शादी के बाद बिंदु ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की और नवंबर 2023 में उनकी नियुक्ति कटरा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय दहटोला पहसौल में हुई। शिक्षिका के पति के बड़े भाई गुरु प्रसाद विश्वकर्मा ने DEO ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है- शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान बिंदु विश्वकर्मा ने स्वयं को अविवाहित बताया था, जबकि उनकी शादी पहले हो चुकी थी। उसने गलत जानकारी देकर सरकारी नौकरी प्राप्त की गई है। मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि नौकरी मिलने के बाद पति-पत्नी के संबंधों में दूरी बढ़ गई। अप्रैल 2025 में प्रवीण विश्वकर्मा पत्नी के साथ रहने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। वहीं, शिक्षिका बिंदु विश्वकर्मा ने बताया कि ससुराल पक्ष की ओर से लगाया गया आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि यह मामला वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस विषय पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद वैवाहिक संबंधों को सामान्य बनाए रखने का प्रयास किया था, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं। उधर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार युवक को रौंदा, हाजीपुर जाते समय हुआ हादसा, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हाजीपुर जा रहे बाइक सवार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक कई फीट दूर जा गिरा। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस बीच ड्राइवर थार छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र के घटारो गांव निवासी सुनील कुमार(25) के तौर पर हुई है। आईडी कार्ड के आधार पर पहचान हुई है। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के बलिया ओवरब्रिज के पास की है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। क्षतिग्रस्त बाइक को भी कब्जे में लेकर थाने पर भेजा गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार ड्राइवर की पहचान की जा सके। कुढ़नी पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

पिकअप ने 11 वर्षीय छात्र को कुचला, घटनास्थल पर ही मौत

लोकतंत्र की शान, पटना

♦ आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया मुआवजे की मांग

पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में 11 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मकसूदपुर के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 11 वर्षीय किशोर को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मकसूदपुर निवासी छोटू पासवान के बेटे राजवीर कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फतुहा–बख्तियारपुर स्टेट हाईवे-106 को जाम कर दिया।

सड़क पार करते समय हुआ हादसा: जानकारी के अनुसार, मृतक राजवीर मकसूदपुर निवासी छोटू पासवान का पुत्र था। शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे राजवीर किसी काम से सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान फतुहा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किशोर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पिकअप वैन मौके से बख्तियारपुर की दिशा में फरार हो गई।

शव रखकर सड़क जाम, मुआवजे की मांग: हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने किशोर के शव को सड़क पर रखकर एसएच-106 को जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। प्रदर्शनकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और वरीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हैं।

पुलिस लोगों को समझाने में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही फतुहा थानाध्यक्ष श्रीमंत सुमन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस घंटों से आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। तनावपूर्ण स्थिति के कारण पुलिस अभी तक शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेज पाई है। थानाध्यक्ष श्रीमंत सुमन ने बताया कि, 'पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है।' उन्होंने आश्वासन दिया कि, 'जल्द ही जाम हटवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।' घटना के बाद मृतक के परिजनों में गहरा शोक है।

पीएम-अजय योजना के तहत कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित, छात्रों को दिए गए सफलता के मंत्र

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: डॉ. अम्बेडकर कल्याण छात्रावास, सहरसा में विभागीय निर्देशानुसार पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) के तहत कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को उनके भविष्य निर्माण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। काउंसलिंग के दौरान छात्रों को सरकारी नौकरी के साथ-साथ उद्यमिता के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन और एकाग्रता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सलाह दी गई। साथ ही डिजिटल शिक्षा के महत्व और उसके प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए छात्रों को इन क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। छात्रों को अध्ययन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित रहने तथा छात्रावास में अनुशासन बनाए रखते हुए अपने करियर को संवारने के लिए प्रेरित किया गया।

'आप पहले कलाकार हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं'

रवि किशन से बोले पवन सिंह, अब सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

लोकतंत्र की शान, पटना

♦ यूजर बोले-यह हमेशा नशे में रहता है

उत्तर प्रदेश के देवरिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह और भाजपा सांसद रवि किशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पवन सिंह ने रवि किशन को प्रधानमंत्री बताया है। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान पवन सिंह ने रवि किशन से कहा, 'आप पहले कलाकार हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं।' उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोगों के बीच हंसी और तालियों का माहौल बन गया। हालांकि, इसके बाद यूजर्स पवन सिंह को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

यह वायरल वीडियो उसी कार्यक्रम का है, जहां भीड़ अनियंत्रित होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।

सोशल मीडिया पर यूजर कर रहे पवन सिंह को ट्रोल: एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि, 'पीने के बाद ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) हो जाता है।' वहीं, सुदर्शन नाम के यूजर ने लिखा कि, 'यह हमेशा नशे में रहता है। जब से MLC बना है, इसका अंदाज और बदल गया है।'

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में आंतरिक ऑडिट को विश्वास और सुशासन का नेतृत्व करना होगा : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

लोकतंत्र की शान

कोलकाता/(मुहम्मद शबीब आलम) : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री रवीन्द्र नारायण रवि ने कहा कि भविष्य केवल उन संस्थानों का नहीं होगा जो तेजी से डिजिटलीकरण करते हैं, बल्कि उन संस्थानों का होगा जो जिम्मेदारी के साथ डिजिटल परिवर्तन को अपनाते हैं। उन्होंने आंतरिक ऑडिट (इंटरनल ऑडिट) पेशे से आह्वान किया कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में विश्वास, जवाबदेही और प्रभावी शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे। राज्यपाल आज नोवोटेल कोलकाता में आयोजित जॉइंट ऑडिट कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स (IIA) इंडिया – कोलकाता चैप्टर ने आईसीएआई (ICAI), आईसीएमएआई (ICMAI), आईसीएसआई (ICSI) और आईसाका (ISACA) के सहयोग से किया था। कॉन्क्लेव का विषय था "इंटरनल ऑडिट : ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस", जबकि उप-विषय था "रीडिफाइनिंग आईए – एआई ऐज़ स्ट्रैटेजिक कंपास"। राज्यपाल ने कहा, "विश्वास वह नींव है जिस पर संस्थान खड़े होते हैं। प्रौद्योगिकी संस्थानों के कामकाज के तरीके को बदल रही है, जबकि परिवर्तनकारी शासन जिम्मेदार प्रगति का मार्गदर्शन करता है। आज संस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे नवाचार और दक्षता को बनाए रखते हुए नैतिकता, पारदर्शिता और जनविश्वास को भी सुरक्षित रखें।" उन्होंने कहा कि आंतरिक ऑडिट अब केवल अनुपालन तक सीमित प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि यह सुशासन, जवाबदेही और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने वाला एक रणनीतिक स्तंभ बन चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक नई क्षमताएं तो प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ विवेकपूर्ण निर्णय और नैतिक जिम्मेदारी भी आवश्यक है।

हुगली नदी पर तैरती 500 नावों पर योग करेंगे 35 हजार लोग, कोलकाता रचेगा इतिहास

लोकतंत्र की शान

कोलकाता (मुहम्मद शबीब आलम) : इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक अद्वितीय नजारा देखने को मिलेगा. कोलकाता इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, और इसका मुख्य आयोजन शहर के प्रसिद्ध रेड रोड पर होगा लेकिन सबसे अनोखा और रिकॉर्ड बनाने वाला प्रदर्शन हुगली नदी के बीचोबीच देखने को मिलेगा, जहां 500 से अधिक नावों पर एक साथ योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है.हुगली नदी पर एक अद्भुत नजारा दिखेगा, जहां कोलकाता के बाबूघाट पर 500 से अधिक यात्री और टूरिस्ट नावें एक साथ एकत्रित होंगी. आयोजन समिति इन सभी नावों को हुगली नदी के पानी में इस तरह से व्यवस्थित करेगी कि आसमान से देखने पर पानी के बीच विभिन्न योग मुद्राओं जैसी सुंदर आकृतियां बनती हुई दिखाई दें. यह अनूठा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल की रिवर कल्चर को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेगा कोलकाता में योग दिवस के इस उत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है. 21 जून के मुख्य कार्यक्रम से पहले शहर में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. इसकी शुरुआत 19 जून को कोलकाता के 11 अलग-अलग स्थानों पर रन टू मेडिटेशन पहल के साथ हो चुकी है. इसके अलावा 'साइकिलिंग फॉर वेलनेस', स्कूलों-दफ्तरों में विशेष सत्र और महिलाओं व बुजुर्गों के लिए खास योग कार्यक्रम तय किए गए हैं.20 जून को हुगली नदी के तट पर सांस्कृतिक संध्या और कला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. यही नहीं, शहर को विशेष रोशनी से सजाया जाएगा और करीब 3,000 ड्रोन्स के माध्यम से एक मेगा ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जो भारत की योग यात्रा और महान योग गुरुओं को समर्पित होगा.पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिलने पर गर्व व्यक्त किया है. उन्होंने कोलकाता को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत का केंद्र बताते हुए कहा कि योग दुनिया को भारत का सबसे अनमोल उपहार है, जो समाज की सभी दीवारों को तोड़कर लोगों को शारीरिक व मानसिक शांति के लिए एक सूत्र में पिरोता है. मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की भी सराहना की, जिसने 'योग 365', 'योग पार्क' और '100 दिनों के मुफ्त ऑनलाइन योग' जैसी पहलों के माध्यम से योग को एक दैनिक जन-आंदोलन बना दिया है.इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश-विदेश की कई जानी-मानी वीआईपी हस्तियां शामिल हो रही हैं. इसलिए मध्य कोलकाता के रेड रोड और मैदान इलाके को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है. कार्यक्रम स्थल और आसपास के चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए खोजी ड्रोन, अत्याधुनिक निगरानी वाहनों और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, सखी वन स्टॉप सेंटर का हुआ उद्घाटन

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता: महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सहरसा में नव निर्मित "सखी वन स्टॉप सेंटर" भवन का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार (भा०प्र०से०) द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने भवन का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित, संवेदनशील एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न एवं अन्य संकट की परिस्थितियों में एक ही स्थान पर परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्सीय सहयोग एवं अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह केंद्र महिला सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन समारोह में संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह पहल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उन्हें सशक्त बनाने के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पटना जू में मैसूर जू से आएगा नर जिराफ

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना जू में मैसूर जू से नर जिराफ आएगा। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जानवरों की अदला-बदली होगी। जिराफ लाने को लेकर पहले कोलकाता जू से बातचीत हुई थी। मगर वहां से फीका रिस्पॉन्स मिला, जिसके बाद मैसूर से जिराफ लाया जाएगा। नर जिराफ को पटना जू लाने का मुख्य उद्देश्य जिराफ के ब्लड लाइन को बदलकर उसके ब्रीडिंग को बढ़ावा देना है। ऐसे में अगर मैसूर जू मांग करेगी तो यहां से तीन साल के मादा शावक जिराफ को मैसूर जू एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेजा जाएगा, क्योंकि पटना जू के पास अभी केवल एक मादा व्यस्क जिराफ मौजूद है।

पटना जू में वर्तमान में चार जिराफ मौजूद: वर्तमान में चार जिराफ पटना जू में हैं, जिनमें दो व्यस्क और दो शावक हैं। व्यस्क और शावक दोनों में एक नर और एक मादा है। व्यस्क नर जिराफ का नाम भीमा और व्यस्क मादा जिराफ का नाम सृष्टि है। वहीं, इसी साल फरवरी में पटना जू में मादा जिराफ 'शांति' की मौत हो गई थी। उसकी उम्र 21 साल थी। पटना जू प्रशासन ने मौत का प्रारंभिक कारण प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बताया था। वर्तमान में शांति के 2 बच्चे "अमन और नंदनी" पटना जू में है।

USA से लाया गया था मादा जिराफ: शांति का जन्म दिनांक 20 जुलाई 2005 को यूएसए के सेन डियागो जू में हुआ था। 2006 में मादा जिराफ को सेन डियागो जू से पटना जू में वन्यजीव अदला-बदली कार्यक्रम के तहत लाया गया था। मादा जिराफ "शांति" के द्वारा 2011 में पटना जू में पहला बच्चा "नव्या" को जन्म दिया गया। 2011 से 2023 तक मादा जिराफ से 6 बच्चों को जन्म दिया गया है।

झारखंड राज्यसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में खटास, कांग्रेस ने जताई नाराजगी

राजेश राम बोले-गठबंधन के साथियों को ना साथ लेना आता, ना देना आता

लोकतंत्र की शान, पटना

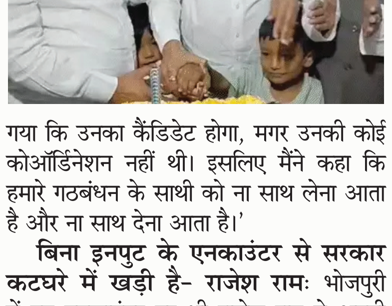

बिहार में महागठबंधन में खटास देखने को मिल रही है। अपने ही सहयोगी पार्टी राजद और माले से कांग्रेस नाराज चल रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, 'हमारे गठबंधन के साथी को ना साथ लेना आता है और ना साथ देना आता है।' झारखंड में हालिया राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के हार के बाद उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव में राजद द्वारा कैंडिडेट के नाम घोषित करने पर भी उन्होंने कहा कि, 'इसमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं था।'

राज्यसभा चुनाव में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था- राजेश राम: राजेश राम ने कहा कि, 'इन तीन राज्यों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारे साथी हमारे साथ नहीं थे। बिहार में संपन्न राज्यसभा चुनाव में केवल व्हिप जारी कर दिया गया कि उनका कैंडिडेट होगा, मगर उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि हमारे गठबंधन के साथी को ना साथ लेना आता है और ना साथ देना आता है।'

बिना इनपुट के एनकाउंटर से सरकार कटघरे में खड़ी है- राजेश राम: भोजपुरी में हुए एनकाउंटर पर भी राजेश राम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'एनकाउंटर शब्द से बिहार लगातार चर्चा में घिरा हुआ है। जब भी एनकाउंटर होता है, तो सरकार के पास गृह विभाग के पास, पुलिस अधिकारियों के पास पूरी तरह से इनपुट होती है। लेकिन अगर बिना इनपुट के एनकाउंटर हो रहे तो सरकार अपने आप कटघरे में खड़ी है।'

आज सदाकत आश्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान छोटे बच्चों के साथ मिलकर राजेश राम ने केक भी काटा। जन्मदिन को लेकर राजेश राम ने कहा कि, मैं राहुल गांधी को जन्मदिन पर बधाई देता हूं। मैं ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जावान और पॉजिटिव शक्तियां हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े।' उन्होंने आगे कहा कि, 'आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। राहुल जी हमारे नेता हैं और जननायक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ट्रक, रेड़ी, ऑटो, बस चलाने वालों के दुख दर्द को देखा और आज पूरे देश में स्टूडेंट की समस्या को लेकर के क्रांति लाने वाले हैं।'

संक्षिप्त समाचार

मेड़ता रोड रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामप्रसाद ओस्तवाल का निधन, कस्बे में छाई शोक की लहर

लोकतंत्र की शान , मेड़ता रोड, एजाज़ अहमद उस्मानी। मेड़ता रोड रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं सामाजिक क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता रामप्रसाद ओस्तवाल का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार करीब 15 दिन पहले घर पर गिर जाने से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए जोधपुर के एक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका

इलाज चल रहा था। उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह करीब छह बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को मेड़ता रोड लाए जाने पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे। परिजनों को सांत्वना देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा। दोपहर करीब तीन बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कस्बे के गणमान्य नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारियों तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। रामप्रसाद ओस्तवाल लंबे समय से मेड़ता रोड रामलीला कमेटी से जुड़े हुए थे और अध्यक्ष के रूप में धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनके सरल, मिलनसार एवं सेवाभावी व्यक्तित्व के कारण वे समाज के विभिन्न वर्गों में सम्मानित थे। उनके निधन को कस्बे के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। श्रद्धांजलि देने वालों ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

मेड़ता रोड जबरेश्वर महादेव मंदिर के पास निर्माण कार्य पर रोक

» एसडीएम ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश
» 22 जून तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश

लोकतंत्र की शान , मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। कस्बे के मेड़ता रोड स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर के समीप रेलवे विभाग द्वारा की जा रही खुदाई और दीवार निर्माण को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच उपखंड मजिस्ट्रेट मेड़ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करते हुए संबंधित निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही रेलवे विभाग, जबरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट एवं संबंधित दुकानदारों को 22 जून 2026 तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रशासन के संज्ञान में आया कि रेलवे विभाग मंदिर के मुख्य द्वार एवं दीवार के समीप खुदाई कर नई दीवार का निर्माण करवा रहा है। इससे मंदिर भवन तथा आसपास स्थित दुकानों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र होने से क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना भी जताई गई है। आदेश में कहा गया है कि मंदिर की दीवार को नुकसान पहुंचने अथवा उसके गिरने की स्थिति में श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच सकती है। इसके अलावा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील बन सकती है। प्रशासन ने बताया कि मौके पर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मेड़ता तथा थानाधिकारी मेड़ता रोड ने रेलवे विभाग के अधिकारियों से सुरक्षित तरीके से कार्य करने तथा विवादित निर्माण रोकने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद कार्य जारी रहने की सूचना मिलने पर यह आदेश जारी किया गया। आदेश में उल्लेख है कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में खसरा संख्या 635, मेड़ता रोड की वर्तमान स्थिति के अनुसार खाता संख्या-1 में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। उपखंड मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेलवे विभाग, जबरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा संबंधित दुकानदार 22 जून 2026 तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे और मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि जिला कलक्टर नागौर, जिला पुलिस अधीक्षक नागौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृत्त मेड़ता, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मेड़ता तथा थानाधिकारी मेड़ता रोड सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित कराई जा सके।

पलवल : स्मैक और गांजा सप्लाई करने वाले दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान , पलवल। जिला सीआईए होडल पुलिस ने नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीआईए होडल प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला 4 जून का है। बहीन थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बाइक सवार आबिद और अकीम को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के दौरान पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्मैक सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गांव गुराकसर का निवासी है। उन्होंने बताया कि दूसरा मामला 6 अप्रैल 2025 का है।

कटनी महिला कांग्रेस द्वारा पुतला दहन विरोध प्रदर्शन

लोकतंत्र की शान हसन रशीद जिला ब्यौरे चीफ़ जबलपुर कटनी मध्यप्रदेश

कटनी : विगत दिनो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आदेशानुसार पर एवं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोसी सेतिया जी के निर्देशन में कटनी जिले में प्रदेश महासचिव एवं शहर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजनी वर्मा जी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा सुश्री मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन को अवैधानिक रूप से निरस्त किए जाने के विरोध में चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार का थाना तिराहा में पुतला दहन किया गया। महिला अध्यक्ष रजनी वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग आज सत्ता पक्ष की कठपुतली बना बैठा है और सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा लगातार महिला विरोधी और जनता विरोधी कार्यों को कर रही है, एक तरफ भाजपा नारी सम्मान की बात करती है तो दूसरी तरफ महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भाजपा की यह दोहरी मानसिकता और जनता को भ्रमित करते हुए महिला विरोधी कार्यों का जीता जागता उदाहरण सुश्री मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा में नामांकन रद्द होना देखा जा सकता है जहां एक ओर किसी भी नामांकन में कोई कमी होने पर हर दावेदार को उस कमी को सुधारने का मौका और समय दिया जाता है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी रही मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फार्म को बिना कोई समय दिए चुनाव आयोग द्वारा यह कहकर निरस्त किया गया कि उनके द्वारा कुछ जानकारी छुपाई गई और जिस जानकारी की बात की गई वह भी गलत थी, मीनाक्षी नटराजन जी को यह कहा गया कि उनके द्वारा नामांकन फार्म में FIR में उनका नाम होने का जिक्र छुपाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट या फिर प्रकरण थाने में दर्ज ही नहीं था केवल जिस FIR की बात की गई उसमें पीड़िता द्वारा यह कहा गया था की उन्होंने संबंधित विषय की

जानकारी मीनाक्षी जी को दी थी जो कि उस समय वहां की तात्कालिक प्रभारी थी, यह घटना तेलंगाना की थी.. बिना तथ्य की जानकारी लिए चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार के द्वारा मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को रद्द करना सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या थी जिसका अधिकार संविधान किसी को भी नहीं देता। भाजपा लगातार महिला विरोधी और जनता के हित विरोध का काम करती जा रही है, और विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर इसका विरोध करती रहेगी। इसके साथ ही महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एसडीएम के हाथों ज्ञापन सोपा जिसमें यह अनुरोध किया की एक महिला होने के नाते राज्यपाल महोदया मीनाक्षी नटराजन जी के साथ हुए इस अन्याय का संज्ञान लेते हुए न्याय करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर जिला अध्यक्ष अमित शुक्ला, ग्रामीण महिला जिला अध्यक्ष माधुरी जैन,पू. कार्यवाहक अध्यक्ष राजा जगवानी, राकेश जैन, विजय पटेल, प्रशांत जैसवाल,सेवादल अध्यक्ष मंगल सिंह, सुमन रजक, आदिता वर्मा, शुभ मंगलानी, मंजू निषाद, लता कनौजिया, मुमताज बानो, सुषमा सिंह, सुनीता सोनी, गीता निषाद, रुक्मणी पांडे,मंजू रजक, शशि यादव, कल्पना पाठक,सुमन,पूजा समुद्री, रूपा तिवारी, दुर्गावती कोल, अर्चना जायसवाल,लता खरे,अजय गोटिया,संजू गुप्ता, नारायण निषाद, राजेश जाटव,मालिनी सिंह, प्रशांत जैसवाल, मारूफ अहमद अभिषेक शिवहरे, जितेंद्र गुप्ता, दिग्विजय सिंह,आफताब अहमद,जॉर्ज डेविड,आनंद पटेल, देवीदीन गुप्ता ,मनोज वर्मा,शिवकुमार यादव, श्याम यादव, मुन्ना कुशवाहा, साहिल नामदेव, श्याम पाहुजा,कमलेश यादव,शशि शेखर भारद्वाज,विजय चंदवानी जमुना प्रसाद विश्वकर्मा, अजय जैसवानी, रमेश अहिरवार, विनोद अहिरवार, हर्षित मिश्रा,दिलदार खान,यूसुफ खान,फरीद मोहम्मद ,मनीष केवट,अभय गौतम,सोनू चौहान,सुरेश लालवानी, अंशु गुप्ता,सलाहुद्दीन खान,अखबर मंसूरी राघव सोनी आदि अनेकों कांग्रेसजन शामिल थे।

असामाजिक तत्वों ने तोड़ी हनुमान जी की प्रतिमा

» अंचल में मूर्ति तोड़कर आस्था में चोट पहुंचाने की दूसरी घटना
» मामले को लेकर थाने में हुई रिपोर्ट, आरोपी गिरफ्तार

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के थाना क्षेत्र मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन डेवा के पास स्थित हनुमान मंदिर में विराजित हनुमान जी की मूर्ति को गुरुवार की दरमियानी रात असामाजिक तत्वों के द्वारा कई टुकड़ों में खंडित कर आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा थाना मझौली में 19 जून को सुबह संदेहियों के नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गईं थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी विशाल शर्मा के द्वारा साइबर सेल के माध्यम से आरोपी चक्रधारी पटेल पिता रामचरित पटेल निवासी

ग्राम डेवा जो आदतन अपराधी है जिसके नाम पहले भी कई मुकदमे पंजीबद्ध है को जिला मुख्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आगे की कार्यवाही जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक इसी तरह ग्राम डेवा के दक्षिणी सीमा जंगल के मध्य सदियों से लोक आस्था एवं धार्मिक केंद्र रहा विजय घाट बघमंडा जहां भगवान शिव पार्वती का मंदिर है एवं मूर्तियां स्थापित है जिसमें पिछले वर्ष मंदिर का गुंबद तोड़ दिया गया था और त्रिशूल व घंटा चोरी कर लिया गया था उस समय भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लेकिन आरोपियों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका है वही अब गांव के बीचों बीच स्थापित प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। सनातन आस्था पर भरोसा रखने वाले ग्रामीणों को इस घटना के बाद ऐसे आसामाजिक तत्वों के घृणित कार्य को लेकर काफी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है एवं ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी मंदिर एवं मूर्ति को खंडित करने की हिमाकत ना हो सके।

इनका कहना है। घटना के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और मुख्य आरोपी चक्रधारी पटेल को जिला मुख्यालय सीधी से गिरफ्तार कर लिया गया है कल तक में उस मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी हो सकती है। विशाल शर्मा, थाना प्रभारी मझौली।

सरकारी भूमि पर प्लाटिंग का बड़ा खेल

» शहर के सीधी खुर्द अंतर्गत का है पूरा मामला
» तत्कालीन कलेक्टर ने शुरू की थी जांच

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिला मुख्यालय में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और प्लाटिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्ष 1980 तक मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज रही भूमि का एक हिस्सा निजी स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि संबंधित भूमि का उपयोग खेल एवं युवक कल्याण विभाग के लिए आरक्षित था। जानकारी के अनुसार खसरा क्रमांक 106/1 पूर्व में मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज था, जो बाद में निजी भूमि के रूप में दर्ज हो गया। वहीं इसी से लगी भूमि खसरा क्रमांक 106/2 वर्तमान में भी मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग के नाम दर्ज है। लगभग 2.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल की यह भूमि खेल एवं युवक कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कराई गई थी। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, लेकिन आरोप है कि तत्कालीन एसडीएम के द्वारा लेनदेन कर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही सरकारी भूमि को अतिक्रमण एवं अवैध बिक्री से बचाने के प्रभावी प्रयास किए गए। आरोप यह भी है कि उक्त भूमि पर प्लाटिंग कर 500 से अधिक लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल सरकारी भूमि के दुरुपयोग का गंभीर मामला होगा, बल्कि सैकड़ों खरीदारों के भविष्य पर भी संकट खड़ा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा राजस्व अभिलेखों की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि शासन की भूमि निजी स्वामित्व में कैसे परिवर्तित हुई। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सूत्रों का दावा है कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई थी और कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। आरोप यह भी लगे हैं कि तत्कालीन एसडीएम द्वारा लेनदेन कर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, छह वाहन जब्त

» रेत-गिट्टी के अवैध परिवहन पर शिकंजा, आदतन कारोबारियों पर NSA की चेतावनी

(ऋचा पाण्डेय, ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाकर रेत एवं गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त छह वाहनों को जब्त किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदतन अवैध खनिज कारोबारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन एवं जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में

जिलेभर में अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17 एवं 18 जून 2026 को रामपुर नैकिन एवं मझौली तहसील क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान संचालित किया गया। जांच के दौरान खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पांच वाहनों तथा खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए एक वाहन को पकड़ा गया। रामपुर नैकिन तहसील के ग्राम बघवार क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त पांच वाहनों तथा मझौली क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त एक वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों में से तीन वाहन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी पिपरांव की अभिरक्षा में, दो वाहन थाना रामपुर नैकिन तथा एक वाहन थाना मझौली के सुपुर्द किए गए हैं। संबंधित वाहन मालिकों एवं चालकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जन सुनवाई के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन

भुगतान के लिए वर्षों से चक्कर लगा रहा संविदाकार

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। विनय कंस्ट्रक्शन कंपनी सीधी के संचालक सीताराम तिवारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सीधी से अपना भुगतान पाने के लिए लंबे अरसे से भटकने को मजबूर हैं। संचालक सीताराम तिवारी ने बताया कि कलेक्टर की जन सुनवाई में वह चार मर्तबा आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगा चुके हैं। कलेक्टर द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी त्र्यंबकेश द्विवेदी द्वारा करने की जरूरत नही समझी जा रही है। उनका देयक रिकार्ड पिछले दो वर्षों से खंड कार्यालय में रखा हुआ है। सुविधा शुल्क न देने की वजह से भुगतान नहीं किया जा रहा है। माप पुस्तिकाएं 1455, 1427, 1448, 1472 में देयक अंकित है लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर की जन सुनवाई में 31 मार्च 2026, 26 मई 2026, 2 जून 2026 एवं 16 जून 2026 को आवेदन दिया गया। जिस पर दिए गए निर्देश बेअसर हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर में जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सुनी जनसमस्याएं

» पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं सरल प्रक्रिया से उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

लोकतंत्र की शान

नागौर/ मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। डेगाना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सांजू में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सहभागिता कर ग्रामीणजनों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना। शिविर के दौरान आमजन ने अपनी विभिन्न समस्याएं,

अपेक्षाएं एवं क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय प्रभारी मंत्री के समक्ष रखे। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक विलंब के सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। कैबिनेट मंत्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य गांव-ढाणी तक पहुंचकर आमजन की समस्याओं को सुनना, उनके समाधान की दिशा में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए जनसमस्याओं के प्रभावी समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक, जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने शिविर के माध्यम से विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाया। ग्रामीण सेवा शिविर में जनभागीदारी, त्वरित समस्या समाधान एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने सुशासन और जनसेवा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया।

वेदांश हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की जांच करने पहुंचे अधिकारी, कई तरह की गड़बड़ियां एवं अनियमितताएं, उजागर

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने मौजूद वेदांश न्यूरो स्पाइन मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का आज अधिकारियों के दल ने निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता रोहन गर्ग द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण विभाग की टीम ने गुरुवार 18 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय के समीप स्थित वेदांश न्यूरो स्पाइन मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान शिकायत से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होने पर विभाग ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के संग्रहण, भंडारण एवं प्रबंधन में अनियमितताओं की शिकायत

विभाग को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और अस्पताल परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। जांच के दौरान बायोमेडिकल वेस्ट सामग्री के भंडारण एवं प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को शिकायत से जुड़े कुछ तथ्य मौके पर सही पाए गए, जिसके आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार कर सक्षम अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिसके बाद पर्यावरण एवं बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई में आर.पी. शुक्ला (वैज्ञानिक), विजय शुक्ला (जिला पर्यावरण अधिकारी), जय शुक्ला (केमिस्ट) सहित विभागीय अमला उपस्थित रहा। विभागीय सूत्रों के अनुसार निरीक्षण में प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं तथा नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यह कार्रवाई जिले में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पर्यावरणीय मानकों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में प्रशासनिक सुधार के नाम पर 18 हजार सरकारी कर्मचारियों की विदाई की तैयारी

काठमांडू। नेपाल सरकार प्रशासनिक सुधार के नाम पर करीब १८ हजार पुराने और अनुभवी कर्मचारियों को समय से पहले घर भेजने की तैयारी में है। अध्यादेश के माध्यम से कानून लाकर चपरासी से लेकर सचिव स्तर तक के लगभग 18 हजार कर्मचारियों को एक साथ अवकाश देने की योजना बनाई जा रही है। यदि यह प्रावधान लागू हुआ तो वर्तमान में कार्यरत केवल 18–20 सचिव ही पद पर बने रहेंगे। इस समय 55 वर्ष आयु पूरी कर चुके सचिवों की संख्या 32 , जबकि 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा कर चुके सचिव 20 हैं। 30 और 55 वर्ष के प्रावधान से प्रभावित न होने वाले विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या केवल 18 है। इनमें हाल ही में उपराष्ट्रपति कार्यालय में स्थानांतरित हुई चन्द्रकला पौडेल, भूमि सचिव मदन भुजेल, पर्यटन सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, लोक सेवा सचिव रामेश्वर दंगाल, युवा, श्रम तथा रोजगार सचिव डॉ. दीपक काफ्ले, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल, सूचना एवं संचार मंत्रालय की लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी तथा ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई क्षेत्र की सचिव सरिता दवाडी शामिल हैं। सहसचिव स्तर के 180 अनुभवी कर्मचारी 55 वर्ष आयु सीमा के कारण अवकाश पर भेजे जाएंगे, जबकि 30 वर्ष सेवा अवधि के कारण 88 राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इन दोनों प्रावधानों से अप्रभावित सहसचिवों की संख्या केवल 75 रह जाएगी। उपसचिव स्तर पर 55 वर्ष आयु सीमा के कारण 501 कर्मचारी और 30 वर्ष सेवा अवधि के कारण 259 कर्मचारी सेवा से बाहर होंगे। इन दोनों प्रावधानों से अप्रभावित राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या केवल 180 है। शाखा अधिकृत स्तर के 2154 कर्मचारी एक साथ प्रभावित होंगे। वहीं, 30 वर्ष सेवा अवधि के कारण राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी के 1947 कर्मचारी अवकाश पर जाएंगे। इस श्रेणी में 1060 कर्मचारी ऐसे हैं जो इन प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे। राजपत्र अनंकित श्रेणी के 2154 कर्मचारी 55 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं, जबकि 1947 कर्मचारी 30 वर्ष सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे। निचले स्तर के 1060 कर्मचारी इन दोनों प्रावधानों से बाहर रहेंगे।

ईरान से अगले कदमों पर वार्ता के लिए जेडी वेंस नहीं रवाना हुए स्विट्जरलैंड

वाशिंगटन। फ्रांस के पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरानी राष्ट्रपति के शांति समझौते के 14 बिंदुओं पर हस्ताक्षर के बाद अगले कदमों पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस गुरुवार रात स्विट्जरलैंड के लिए रवाना नहीं हुए। इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने की है। हालांकि दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के बाद मध्य पूर्व में तनाव काफी हद तक कम हुआ है और ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम बातचीत का रास्ता साफ हुआ है। सीबीएस न्यूज और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, वेंस के यात्रा स्थगित करने से होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों और जहाजों के आवागमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के बाद होर्मुज खुल गया है।

आवागमन में अचानक तेजी आ गई है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ बातचीत शुरू करने में मदद के लिए गुरुवार देररात स्विट्जरलैंड के लिए रवाना नहीं हुए। प्रवक्ता ने कहा कि वेंस फोन कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि तकनीकी बातचीत की योजना अभी तय नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्ष, तकनीकी बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस के नेताओं को ईरान समझौते के बारे में जानकारी दी है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाउस और सीनेट के नेताओं के साथ फोन पर इस समझौते के बारे में बताया। अधिकारियों ने सीनेट की विदेश संबंध समिति और हाउस की विदेश मामलों की समिति के शीर्ष सांसद साथ ही सीनेट में बहुमत दल के नेता जॉन थ्यून और अल्पसंख्यक दल के नेता चक शूमर को फोन किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सांसदों के सवालों के जवाब भी दिए और अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली आगामी बातचीत की रूपरेखा बताई। इस बीच ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ हुए अमेरिकी समझौते के बावजूद दक्षिणी लेबनान में अपने सुरक्षा क्षेत्र से इजराइली सेना को हटाने का कड़ा विरोध किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइली सेना को लेबनान की जमीन छोड़नी होगी। उधर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा ली है। तेहरान का कहना है कि होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को परमिट जारी करने की जिम्मेदारी उसकी 'पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' को सौंपी गई है।

हिमालय क्षेत्र में बनेगा देश का नया जलवायु निगरानी केंद्र

नई दिल्ली। हिमालय क्षेत्र में देश का नया जलवायु निगरानी केंद्र बनने जा रहा है। यह कदम जलवायु अनुसंधान को मजबूती प्रदान करेगा। इस संबंध में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एआरआईईएस) नैनीताल के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 50 वर्षों से अधिक अवधि के लिए मान्य होगी। समझौते के तहत उत्तराखंड के देवस्थल वेधशाला में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क (बीसीओएन) के अंतर्गत दीर्घकालिक जलवायु अवलोकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी जानकारी के अनुसार यह केंद्र हिमालयी क्षेत्र में मौसम, ग्रीनहाउस गैसों, वायुमंडलीय प्रदूषकों और मिट्टी की नमी जैसे महत्वपूर्ण मानकों की निगरानी करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, देवस्थल का स्वच्छ और ऊंचाई वाला वातावरण जलवायु परिवर्तन से जुड़े अध्ययनों के लिए बेहद उपयुक्त है। यहां से प्राप्त आंकड़े हिमालयी क्षेत्र में जलवायु प्रक्रियाओं को समझने और प्रदूषण के प्रभावों का आकलन करने में मदद करेंगे। बीसीओएन परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर में उच्च-गुणवत्ता वाला जलवायु डेटा तैयार करना और जलवायु परिवर्तन पर शोध को बढ़ावा देना है। नेटवर्क से प्राप्त आंकड़े भारत के जलवायु मॉडल और भविष्य के मौसम एवं जलवायु पूर्वानुमानों को अधिक सटीक बनाने में भी सहायक होंगे। यह पहल भारत को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और वैज्ञानिक आधार पर नीति निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

तृणमूल नेता गौतम देव ने सिलीगुड़ी के मेयर पद से दिया इस्तीफा

सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफे दे दिया है। जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला पार्टी नेतृत्व को पहले ही बता दिया था। जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को प्रशासन के पास औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। हाल ही में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग जिला (समतल) कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि वह संगठनात्मक कामकाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं। सूत्रों की मानें तो बदले राजनीतिक परिस्थितियों में प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है। गुरुवार को मेयर परिषद के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। गौतम देव का राजनीतिक करियर काफी अहम रहा है। 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें उत्तर बंगाल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 2016 में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें पर्यटन मंत्री बनाया। हालांकि, 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2022 में सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें मेयर बनाया गया था। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में सिलीगुड़ी सीट से उन्हें फिर हार झेलनी पड़ी और शहर के सभी वार्डों में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर अंदरूनी नाराजगी भी सामने आई। इसी के बाद से उनके मेयर पद छोड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी।

'सतत कृषि से पूर्वोत्तर बन सकता है भारत की अगली विकास शक्ति'

एजेंसी, शिलांग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सतत कृषि, प्रीमियम जैविक उत्पादों और पर्यावरण-अनुकूल विकास के बल पर भारत की अगली विकास शक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक कृषि पद्धतियां इसे वैश्विक बाजार में विशेष पहचान दिलाने की क्षमता रखती हैं। मेघालय के री-भोई जिले के भोइरिमबोंग में ईस्टर्न री-भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन के बाद शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि का भविष्य केवल अधिक उत्पादन करने वालों का नहीं, बल्कि बेहतर, स्वच्छ, विश्वसनीय और ट्रेस करने योग्य उत्पाद उपलब्ध कराने वालों का होगा।

उन्होंने कहा कि मेघालय को जैविक खेती के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान प्राप्त है। राज्य के कृषि उत्पादों और पारंपरिक खेती पर उपभोक्ताओं का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन्हें बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां विश्वास स्वयं एक मूल्यवान संपत्ति बन चुका है और मेघालय इस दृष्टि से अत्यंत मजबूत स्थिति में है। सीतारमण ने कहा कि मेघालय की बढ़ती मसाला अर्थव्यवस्था यह साबित करती है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास की प्रक्रिया प्रकृति की कीमत पर नहीं होनी चाहिए और मानव समाज को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना होगा।

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत' के निर्माण में देश के प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। उनके अनुसार, पूर्वोत्तर इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में केंद्रीय भूमिका निभाएगा और भविष्य में देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। वित्त मंत्री ने कहा कि बेहतर प्रसंस्करण सुविधाएं और मजबूत उत्पादक सहकारी संस्थाएं किसानों, विशेषकर पारंपरिक कृषि से जुड़ी महिलाओं को अधिक लाभ दिलाने में सहायक होंगी। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

नवनिर्मित मसाला प्रसंस्करण संयंत्र से लाकाडोंग हल्दी, अदरक और काली मिर्च जैसी फसलों के उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। यह परियोजना राज्य के जैविक कृषि तंत्र को मजबूत करने, कृषि निर्यात बढ़ाने तथा क्षेत्र में टिकाऊ आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

दिल्ली के पहले महिला पुलिस स्टेशन का शुभारंभ

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस कदम का मकसद महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके ख़िलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के तरीके को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और सशक्त महिला ही प्रगतिशील समाज की नींव होती है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ लक्ष्मी सिंह मौजूद रहीं।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन से प्रेरित होकर कि 'नारी शक्ति' ही राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला है, यह महत्वपूर्ण संस्थान महिलाओं को बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज कराने, न्याय पाने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की

महिला-सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख पहलों, जैसे 'पिंक बूथ' और 'सशक्ति' अभियान की भी समीक्षा की। पुलिस बल को राजधानी में ऐसे और केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि महिला-अनुकूल पुलिसिंग और तत्परता से कानून लागू करने की दिशा में एक नया मानक स्थापित किया जा सके।

उपराज्यपाल ने कहा कि एक सुरक्षित और सशक्त महिला ही प्रगतिशील समाज की नींव होती है। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, समावेशी और सशक्त विकसित दिल्ली के निर्माण की दिशा में काम करते रहेंगे। अगर हम कोई अपराध होते या अपनी माताओं, बहनों और परिवार के साथ अन्याय होते देखें तो जरूर आवाज उठाएं या पुलिस को सूचित करें। यह एक ऐसा सीधा जरिया है जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध से सीधे निपटेगा।

पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने तृणमूल के सभी पदों से इस्तीफा दिया

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ रही पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को शुक्रवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, ज्योतिप्रिय मल्लिक ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि वह पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके कारण अब संगठन की जिम्मेदारियां निभा पाना उनके लिए संभव नहीं है।

हाल ही में ज्योतिप्रिय मल्लिक को तृणमूल कांग्रेस की कार्यकारी समिति में जगह दी गई थी लेकिन

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने में असमर्थता जताई है।

उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिप्रिय मल्लिक लंबे समय से तृणमूल के कद्दावर नेताओं में गिने जाते रहे हैं। वे पार्टी संगठन एवं तृणमूल सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में जारी उठा पटक के बीच ज्योतिप्रिय के इस्तीफे को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा को लेकर आयोग ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी

एजेंसी, नई दिल्ली

महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक एडवाइजरी जारी की है। शुक्रवार को आयोग की तरफ से जारी एडवाइजरी में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम (पोश एक्ट), 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश की गई है। एडवाइजरी में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों में वार्षिक पोश ऑडिट अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है।

आयोग की तरफ से जारी परामर्श में राज्यों को पोश मॉनिटरिंग सेल या डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित कर कानून के अनुपालन की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। आयोग ने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, शैक्षणिक

संस्थानों, अस्पतालों और निजी प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही, असंगठित क्षेत्र, घरेलू कामगारों और छोटे प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए स्थानीय समितियों को मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है।

एडवाइजरी में ब्लॉक, तहसील और नगर स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, पोश कानून के प्रति जागरूकता अभियान, समिति सदस्यों के प्रशिक्षण तथा शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ना और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी शामिल हैं। आयोग ने केंद्र सरकार के शी बॉक्स पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने तथा शिकायत प्रक्रिया और समिति संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने पर भी बल दिया है।

आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन उपायों से देशभर में महिलाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और लैंगिक संवेदनशील कार्यस्थल संस्कृति विकसित होगी तथा कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम और प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

जयराम रमेश ने 'ग्रेट निकोबार' से जुड़ी पर्यावरणीय मंजूरी और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के कथित अभाव का मुद्दा उठाया

एजेंसी, नई दिल्ली

पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने 'ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना' को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को एक बार फिर पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के अभाव को लेकर भूपेंद्र यादव द्वारा विगत 13 जून को भेजे गए जवाब को पूरी तरह निराशाजनक और असंतोषजनक करार दिया है। जयराम रमेश ने शुक्रवार को पत्र में कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना के विभिन्न पहलुओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पूरी तरह से अपर्याप्त है। यह स्वयं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तय किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री के पास उनके द्वारा पहले उठाए गए तकनीकी, कानूनी और वैज्ञानिक सवालों का कोई ठोस अथवा संतोषजनक जवाब नहीं है। सरकार केवल अपनी पुरानी बातों को दोहराकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक परियोजना की छमाही अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिए, लेकिन मार्च 2024

के बाद से ऐसी कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। यही नहीं, परियोजना निगरानी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भी बैठक संपन्न होने के कई महीनों बाद वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।

रमेश ने कहा कि 11 नवंबर 2022 को जारी की गई पर्यावरणीय मंजूरी के तहत 15 दिनों के भीतर विभिन्न संरक्षण और शमन योजनाएं जमा की जानी थीं। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) और अंडमान-निकोबार वन विभाग जैसी देश की शीर्ष संस्थाओं द्वारा तैयार ये महत्वपूर्ण योजनाएं आज तक सार्वजनिक पटल पर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

उन्होंने सवाल किया कि पर्यावरण मूल्यांकन समिति के सुझावों के बाद कुछ संस्थानों से इन योजनाओं के संशोधित प्रस्ताव मांगे गए थे। यह बेहद अजीब और संदेहास्पद है कि ये योजनाएं संबंधित समिति द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद सौंपी गईं, जिससे इनकी पर्याप्तता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। साथ ही, विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए कम से कम 12 अध्ययनों पर आधारित अद्यतन पर्यावरण प्रबंधन योजना को भी जनता से पूरी तरह छिपाकर रखा गया है। रमेश ने आरोप लगाया कि परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण और बुनियादी अध्ययन अभी भी लंबित हैं, जो साफ तौर पर यह साबित करता है कि इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी बहुत जल्दबाजी, अपरिपक्व और राजनीतिक दबाव में दी गई है। उन्होंने वैज्ञानिक तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि परियोजना क्षेत्र से मूंगा चट्टानों को बड़े पैमाने पर दूसरी जगह स्थानांतरित करने जैसी शमन योजनाएं पूरी तरह से अवास्तविक और धरातल पर लगभग असंभव हैं।

कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि उन्होंने पहले भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी, लेकिन सरकार उसे भी दबाने का प्रयास कर रही है।

गुजरात के पावागढ़ में पहाड़ी से गिरीं चट्टानें, दो श्रद्धालुओं की मौत

एजेंसी, पंचमहल

गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पावागढ़ में शुक्रवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ी स्थित पाटियापुल के समीप अचानक चट्टानें और मलबा गिरने से कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक दो श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है जबकि मलबे में फंसे पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि मानसून की शुरुआती बारिश के बीच पावागढ़ पहाड़ी पर पानी का तेज बहाव था। इसी दौरान पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर और मलबा खिसककर नीचे आ गया। उस समय पाटियापुल के पास से गुजर रहे श्रद्धालु अचानक आए मलबे की चपेट में आ गए। इसके कारण मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। स्थानीय सरपंच पति रवि गढ़वी ने बताया कि हादसे की सूचना पर पावागढ़ रोप-वे की इमरजेंसी रेस्क्यू टीम और हालोल फायर

विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया गया। फायर विभाग की टीम ने पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए हालोल रेफरल अस्पताल पहुंचाया जबकि दो श्रद्धालुओं की मौत हो गयी।

स्थानीय सरपंच पति रवि गढ़वी ने बताया कि सूचना पर पुलिस का दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य तेज गति से संचालित किया गया। इसके बाद मलबे में फंसे पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अपहृत व्यक्ति को बचाया, नौ उग्रवादी गिरफ्तार

एजेंसी, इम्फाल

मणिपुर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने अलग-अलग अभियानों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अपहृत व्यक्ति को सुरक्षित मुक्त कराया तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों से जुड़े नौ सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, तेंगनौपाल जिले के मोरेह थाना क्षेत्र के गेट नंबर-1 इलाके से सुरक्षा बलों ने गुरुवार नगामसोम बैते (50) को सुरक्षित बरामद किया। बी. बोंगजांग गांव निवासी बैते का कथित तौर पर पीएसएच के संदिग्ध उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया था। बचाव अभियान के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया।

इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने काकचिंग जिले के विभिन्न स्थानों से केसीपी (एमएफएल) के चार सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मोइरांगथेम तोंडोम्बा सिंह उर्फ टेमे (44),

वाहेंगबाम इनाओ सिंह उर्फ जैक (46), नोंगमैथेम डेविड मैतेई (42) और माईबाम लोकेंद्र सिंह (38) के रूप में हुई है। ये उग्रवादी रंगदारी वसूली और अवैध हथियार आपूर्ति के नेटवर्क में शामिल थे। मणिपुर पुलिस ने इंफाल पूर्व जिले से केसीपी के चार सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया। इन पर इंफाल पूर्व के विभिन्न इलाकों में, जिसमें ब्रह्मापुर नहाबाम बामोन लैकाई स्थित एक आवास भी शामिल है, हैंड ग्रेनेड रखने का आरोप है। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान हुइद्रोम पालिनबा सिंह उर्फ नानाओ, पेबाम रोशन सिंह, नामेइराकपाम जित्सोन मैतेई व माइमोम लेम्बा मैतेई के रूप में हुई है।

पारंपरिक सैन्य क्षमताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी पहले थीं: राजनाथ सिंह

नागपुर में 10 हजार टन क्षमता वाली एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का उद्घाटन

एजेंसी, नागपुर

रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि अत्याधुनिक एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह परियोजना स्वदेशी तकनीक और उत्पादन क्षमताओं का नया अध्याय लिखेगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक सैन्य क्षमताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। राजनाथ सिंह शुक्रवार को नागपुर के अंबाझरी ऑर्डनेंस फैक्टरी परिसर में 10 हजार टन क्षमता वाली अत्याधुनिक एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना के आधारशिला रखने के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह परियोजना भारत की बदलती

और आत्मविश्वास से भरपूर सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिन आवश्यकताओं के लिए पहले भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज उन्हें देश के उद्योग और नागरिक स्वयं पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है वही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों और युद्धों के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों का उत्पादन देश के भीतर ही होना अत्यंत आवश्यक है।प्रस्तावित एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना को रक्षा उत्पादन क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति माना जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से रक्षा, एयरोस्पेस और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक उच्च क्षमता और उच्च सटीकता वाले एल्युमिनियम मिश्रधातु उत्पादों का बड़े पैमाने पर देश में निर्माण किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना भारत के रक्षा औद्योगिक बुनियादी ढांचे को और अधिक सशक्त बनाने के साथ-साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से महत्वपूर्ण एल्युमिनियम घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026- "स्वस्थ आयु के लिए योग",योग 365 "अभियान", 21 दिन 21 मिनट" अभियान का आगाज़ - स्वस्थ आयु, स्वस्थ भविष्य और स्वस्थ विश्व का महामंत्र -समग्र व्यापक विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» योग किसी धर्म, भाषा, संस्कृति या सीमा में बंधा नहीं है, यह मानवता के लिए भारत का वह अमूल्य उपहार है जिसने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया है।

» 12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ और सुखी जीवन के वैश्विक संकल्प के रूप में स्वीकार करने का प्रण करने का शुभ अवसर है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 21 जून 2026 को पूरा विश्व 12वें अंतरराष्ट्रीय योगदिवस का उत्सव मना रहा है।आज योग केवल भारत की प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप बन चुका है।संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में मान्यता मिलने के बाद योग ने जिस गति से विश्वभर में अपनी पहचान बनाई है,वह मानव इतिहास की सबसे सफल सांस्कृतिक और स्वास्थ्य यात्राओं में से एक मानी जा सकती है। आज दुनियाँ के लगभग हर देश में योग का अभ्यास किया जा रहा है और करोड़ों लोग इसे स्वस्थ जीवन शैली का आधार मान रहे हैं।इस वर्ष 2026 का मुख्य विषय "स्वस्थ आयु के लिए योग" रखा गया है। यह विषय केवल लंबी आयु प्राप्त करने की बात नहीं करता, बल्कि इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति बढ़ती उम्र में भी सक्रिय, आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहे। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र दावे के साथ कह सकता हूं क्रि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब यह स्वीकार कर रहा है कि नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को संतुलित करने,तनाव कम करने, हृदय स्वास्थ्य बेहतर बनाने तथा मानसिक स्फूर्ति बनाए रखने में अत्यंत सहायक हैं।वर्ष 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता इस अवसर पर योग की वैश्विक राजधानी जैसा स्वरूप धारण कर चुका है।लाखों लोगों की भागीदारी, विशाल सामूहिक योगाभ्यास, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आधुनिक तकनीक के समावेश ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया है। साथियों, इस वर्ष योग दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण योग संगम है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 11 सफल वर्षों के बाद 12वें संस्करण में देशभर के हजारों स्थानों पर एक साथ कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर सामूहिक योग प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।यह केवल भारत तक सीमित नहीं है,बल्कि दुनियाँ के अनेक देशों में भी समान समय पर योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।यह दृश्य वास्तव में एक पृथ्वी,एक स्वास्थ्य,एक मानवता कीभावना को साकार करता है।2026 के आयोजन की एक और विशेषता डिजिटल भागीदारी है। मायभारत प्लेटफॉर्म और योग संगम पोर्टल के माध्यम से लाखों नागरिकों ने पंजीकरण कर इस वैश्विक उत्सव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। डिजिटल तकनीक ने योग को गांवों से महानगरों तक और भारत से विश्व के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योग दिवस तकनीक और परंपरा के अद्भुत समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। साथियों, इस बार विशेष रूप से बुजुर्गों और अति बुजुर्गों के लिए योग को केंद्र में रखा गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा ऐसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो जोड़ों के स्वास्थ्य, संतुलन लचीलेपन,श्वसन क्षमता और मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं। आज जब दुनियाँ तेजी से वृद्धावस्था की ओर बढ़

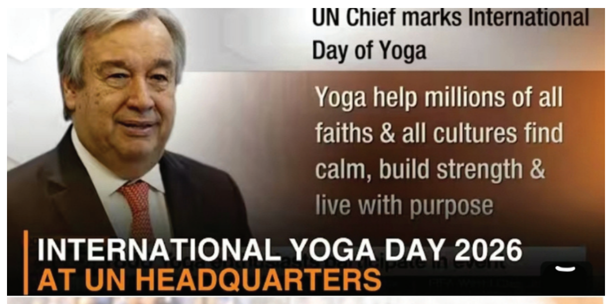

रही है, तब स्वस्थ आयु के लिए योग का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। बढ़ती उम्र को बीमारी का पर्याय मानने के बजाय सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा योग प्रदान करता है। साथियों, योग दिवस 2026 का एक अद्भुत आकर्षण कोलकाता में हुगली नदी पर लगभग 500 नावों पर सामूहिक योगाभ्यास तथा लगभग 3000 ड्रोन द्वारा प्रस्तुत मेगा ड्रोन शो है। परंपरा और आधुनिक तकनीक का यह संगम दुनिया को यह संदेश देता है कि योग केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता भी है। ऐसे भव्य आयोजन युवाओं और बच्चों में योग के प्रति आकर्षण बढ़ाने में भी रूप से सहायक सिद्ध हो रहे हैं। साथियों, विश्व स्तर पर योग की बढ़ती लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण हाल ही में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 है। अहमदाबाद में आयोजित इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने इस प्रतियोगिता में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक जीते, जिनमें 102 स्वर्ण पदक शामिल थे। भारत विश्व पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा और योगासन खेल के क्षेत्र में अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता सिद्ध की।प्रतियोगिता में भारत ने 102 स्वर्ण पदकों के अतिरिक्त शेष पदक रजत और कांस्य के रूप में प्राप्त किए तथा विश्व योगासन मंच पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की।विश्व योगासन चैंपियनशिप की यह सफलता केवल खेल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि योग भारत की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ-साथ एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में भी विकसित हो रहा है। आज अनेक देशों के युवा योगासन को खेल, फिटनेस और मानसिक विकास के माध्यम के रूप में अपना रहे हैं। इससे योग को भविष्य में बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में और अधिक स्थान मिलने की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। साथियों, आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा "योग 365" अभियान इस वर्ष विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि योग केवल 21 जून का कार्यक्रम नहीं, बल्कि वर्ष के सभी 365 दिनों की जीवनशैली होना चाहिए। यदि योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाए तो मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, तनाव, अवसाद और अनिद्रा जैसी अनेक समस्याओं से बचाव संभव है। युवाओं के लिए, "21 दिन, 21 मिनट" अभियान भी अत्यंत प्रेरणादायक पहल सिद्ध हुआ है। मायभारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को प्रतिदिन कम से कम 21 मिनट योग करने के लिए प्रेरित किया गया है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है, वहां योग मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। छात्रों के लिए योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक मानसिक कवच है जो एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता को बेहतर बनाता है। साथियों, योग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सार्वभौमिकता है।यह किसी विशेष धर्मसंप्रदाय या विचारधारा से जुड़ा नहीं है। योग मानव शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। यही कारण है कि आज अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका सहित विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में योग को अपनाया जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा भारतीय मिशनों के माध्यम से 210 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 2500 से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो इसकी वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण हैं।आज दुनिया जिस प्रकार जीवनशैली संबंधी रोगों, मानसिक तनाव, अकेलेपन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, उस परिस्थिति में योग एक व्यापक समाधान प्रस्तुत करता है। योग शरीर को शक्ति देता है, मन को स्थिरता देता है और जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी योग को निवारक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। साथियों, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाओं से नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली से निर्मित होता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम और ध्यान को दें, तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि हमारा समाज भी अधिक संतुलित, सकारात्मक और उत्पादक बनेगा।"उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहकर जीना हमारी पसंद हो सकती है।' 'स्वस्थ आयु के लिए योग' केवल एक नारा नहीं, बल्कि विश्व के करोड़ों बुजुर्गों को सम्मानजनक, सक्रिय और खुशहाल जीवन देने का वैश्विक अभियान है।"

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 केवल एक तिथि नहीं, बल्कि मानवता के लिए स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का महापर्व है। आइए हम संकल्प लें कि योग को केवल 21 जून तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन के प्रत्येक दिन का हिस्सा बनाएंगे। यही स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ समाज और विकसित विश्व की सबसे मजबूत नींव है।आइए,योग को अपनाएं, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और 365 दिन योग के साथ एक नए, ऊर्जावान, संतुलित और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यहीअंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का वास्तविक संदेश है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

आखिरी आदमी की सांसों में बसा कर्मयोद्धा नेता

लेखक- ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहते, वे एक युग का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व ऐसा ही एक युगबोध बनकर उभरा है। जून 2026 मीं उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि केवल दिनों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उस विश्वास, जनसमर्थन और विकास-यात्रा का प्रतीक है, जिसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन-प्रणाली और वैश्विक छवि को नई दिशा दी है। लोकतंत्र में किसी नेता की वास्तविक सफलता उसके पद की अवधि से नहीं, बल्कि उसके कार्यों के प्रभाव से मापी जाती है। यदि शासन की कसौटी अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है, तो मोदी युग का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने विकास को सरकारी फाइलों और घोषणाओं से निकालकर सामान्य नागरिक के जीवन तक पहुंचाया है। यह वही अवधारणा है जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 'अंत्योदय' कहा था-समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लंबी विकास यात्रा तय की है। जवाहरलाल नेहरू ने नवस्वतंत्र भारत की संस्थागत नींव रखी। लोकतंत्र, वैज्ञानिक चिंतन, सार्वजनिक संस्थानों, शिक्षा, अनुसंधान तथा औद्योगिक विकास की आधारशिला उन्हीं के समय में रखी गई। किंतु समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि योजनाएं बनाना और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। दशकों तक सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों के बीच बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी रही, जिसके कारण विकास का बड़ा हिस्सा रास्ते में ही समाप्त हो जाता था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। आर्थिक सुस्ती, भ्रष्टाचार के आरोप, अधूरी परियोजनाएं, प्रशासनिक जड़ता और जनता में घटता विश्वास प्रमुख चिंताएं थीं। ऐसे समय में उन्होंने शासन की परंपरागत शैली को बदलते हुए तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही को केंद्र में रखा। यह परिवर्तन केवल नीतियों का नहीं, बल्कि शासन के दर्शन का परिवर्तन था। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली का विस्तार है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल तकनीक को जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था विकसित की गई, जिसने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना संभव बनाया। इससे न केवल भ्रष्टाचार और रिसाव में कमी आई, बल्कि करोड़ों लोगों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि सरकार वास्तव में उनके द्वार तक पहुंच सकती है। गरीब, किसान, महिला, छात्र, वृद्ध और श्रमिक-सभी वर्गों को इसका लाभ मिला। वित्तीय समावेशन की दिशा में जनधन योजना ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जिन परिवारों के पास कभी बैंक खाता नहीं था, वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने। यह केवल बैंक खाते खोलने की योजना नहीं थी, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण का एक नया अध्याय था। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से भरे रसोईघरों से मुक्ति दिलाई। स्वच्छ ईंधन ने उनके स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन किया। मोदी युग की एक बड़ी पहचान आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार भी है। सड़कों, एक्सप्रेस-वे, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के क्षेत्र में जिस गति से कार्य हुआ, उसने विकास को नए पंख दिए। आज छोटे शहर भी हवाई संपर्क से जुड़ रहे हैं। गांवों तक सड़कें पहुंच रही हैं। रेलवे का तीव्र आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई हैं। आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए। जिन लोगों ने वर्षों तक कच्ची झोपड़ियों में जीवन बिताया, उनके लिए अपना घर केवल एक भवन नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया। शौचालय निर्माण अभियान ने स्वच्छता को जनांदोलन का रूप दिया। ये परिवर्तन केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जीवन स्तर में दिखाई देते हैं। कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने किसानों के लिए आय के नए अवसर खोले हैं। किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ऊर्जादाता के रूप में भी उभर रहे हैं। जैव ईंधन, प्राकृतिक खेती, कृषि अवसंरचना और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के प्रयास किए गए हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है।

दल-बदल की राजनीति और लोकतंत्र का भविष्य जनादेश की चोरी या राजनीतिक अवसरवाद जनादेश बनाम दल-बदल|भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक अवसरवाद का बंधक बनता जा रहा है?

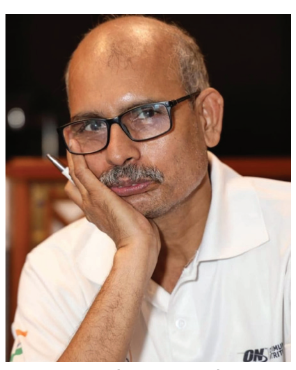
आलेख-विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला',स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जनता को लोकतंत्र का वास्तविक स्वामी माना जाता है। संविधान की मूल भावना भी यही है कि सत्ता का स्त्रोत जनता है और जनादेश सर्वोपरि है।मतदाता किसी प्रत्याशी को केवल उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं चुनता, बल्कि उसके राजनीतिक दल, विचारधारा,नेतृत्व और चुनावी घोषणापत्र पर विश्वास व्यक्त करता है।यही कारण है कि चुनाव परिणाम केवल सीटों की गणना नहीं,बल्कि जनता की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में जिस प्रकार दल-बदल की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसने लोकतंत्र की आत्मा जनादेश की पवित्रता और राजनीतिक नैतिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।एक ओर केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। विकसित भारत,आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत जैसे लक्ष्य राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दलों के भीतर बढ़ती अस्थिरता,वैचारिक प्रतिबद्धता का क्षरण और सत्ता प्राप्ति की बढ़ती होड़ लोकतंत्र को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर रही है।जनता जिन प्रतिनिधियों को किसी दल के प्रतीक चिन्ह पर चुनकर भेजती है,वे अनेक बार कुछ वर्षों बाद या कभी-कभी कुछ महीनों बाद ही दल बदल लेते हैं। इससे सबसे अधिक आघात मतदाता के विश्वास को पहुंचता है। भारतीय राजनीति में दल-बदल की समस्या नई नहीं है।वर्ष 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में कई बार पार्टी बदलने की घटना के बाद "आया राम,गया राम" भारतीय राजनीति का स्थायी मुहावरा बन गया। 1967से1971के बीच देशभर में पांच सौ से अधिक विधायकों द्वारा दल बदलने की घटनाएं दर्ज की गईं।राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।इसी के परिणामस्वरूप वर्ष 1985 में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची अर्थात दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया। बाद में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे और कठोर बनाया गया।कानून बनने के बावजूद समस्या समाप्त नहीं हुई।नेताओं ने कानून की कमियों को समझ लिया और व्यक्तिगत दल-बदल के स्थान पर सामूहिक टूट,विलय और इस्तीफों की रणनीति अपनाई।आज स्थिति यह है कि सरकारें कई बार चुनावी जनादेश से कम और राजनीतिक प्रबंधन से अधिक बनती-बिगड़ती दिखाई देती हैं।राजनीतिक सुधारों के लिए कार्य करने वाली संस्था एडीआर(ऐशोसिएसन फॉर ड्रेमोक्रिऐसी रिफॉर्स)की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच देशभर में 405 विधायक दल बदलकर दोबारा चुनाव मैदान में उतरे।इनमें से 182 विधायक अर्थात लगभग 45 प्रतिशत एक ही दल में शामिल हुए। इसी अवधि में 170 विधायक कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में चले गए जबकि केवल 18 विधायक भाजपा छोड़कर अन्य दलों में गए। एडीआर ने यह भी उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश,गोवा,मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकारों के गिरने के पीछे विधायकों का दल-बदल प्रमुख कारण रहा।महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र में दल-बदल की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनकर सामने आया। वर्ष 2022 में शिवसेना के 55 में से लगभग 40 विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अलग हो गए।इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी टूट हुई और अजित पवार गुट अलग हो गया। जनता ने जिस महाविकास आघाड़ी या जिस राजनीतिक संरचना को वोट दिया था,कुछ ही वर्षों में उसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि महाराष्ट्र ने भारतीय राजनीति में "विधायक आधारित सत्ता परिवर्तन" का नया मॉडल प्रस्तुत किया है।इससे यह प्रश्न और प्रबल हुआ कि लोकतंत्र में वास्तविक महत्व मतदाता के वोट का है या निर्वाचित प्रतिनिधियों की बाद की राजनीतिक निष्ठाओं का।मध्य प्रदेश का उदाहरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद 22कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।परिणामस्वरूप कमलनाथ सरकार गिर गई और राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया।बाद में इनमें से अधिकांश नेता दूसरे दल के टिकट पर पुनः चुनाव लड़े।यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में दल-बदल और सत्ता परिवर्तन के सबसे चर्चित उदाहरणों में गिना जाता है।कर्नाटक में वर्ष 2019 में 17विधायकों के इस्तीफे ने एच.डी. कुमारस्वामी सरकार को गिरा दिया।कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया और नई सरकार का गठन हुआ।राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भी दल-बदल कानून की सीमाओं का उदाहरण बताया।गोवा,मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी निर्वाचित विधायकों के दल बदलने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए।कई बार विपक्ष सत्ता पक्ष में बदल गया और कई बार सत्तारूढ़ दल विपक्ष में पहुंच गया।इससे लोकतांत्रिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। एडीआर की रिपोर्ट ने भी इन राज्यों में सरकार परिवर्तन के पीछे दल-बदल को प्रमुख कारण बताया है।पश्चिम बंगाल में भी दल-बदल की राजनीति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।वर्ष 2021 के विधान सभा चुनाव से पहले और बाद में तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा के बीच नेताओं और विधायकों का आना-जाना जारी रहा। राजनीतिक गलियारों में समय-समय पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों की नाराजगी और संभावित टूट की चर्चाएँ भी उठती रही हैं।लोकतंत्र के लिए केवल दल-बदल ही समस्या नहीं है, बल्कि लगातार बनी रहने वाली राजनीतिक अनिश्चितता भी चिंता का विषय है।दिल्ली और पंजाब की राजनीति में भी इस विषय ने नया आयाम ग्रहण किया है।आमआदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ नेतृत्व के सार्वजनिक मतभेद सामने आए। राज्यसभा तक पहुंचे कुछ नेताओं और पार्टी नेतृत्व के बीच खुला टकराव राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना।इससे यह बहस तेज हुई कि क्या राजनीतिक दलों के भीतर वैचारिक लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और क्या जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही केवल दल के प्रति है या मतदाताओं के प्रति भी।पंजाब में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ राजनीतिक पुनर्संरेखण की चर्चाएँ तेज हो चुकी हैं।कांग्रेस,आम आदमी पार्टी, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच नेताओं के संभावित स्थानांतरण को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा, समाजवादी पार्टी,बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस आगामी विधान सभा चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक विस्तार में लगी हुई हैं।राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं और विधायकों के दल बदलने की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।यद्यपि यह अभी राजनीतिक विश्लेषण का विषय है,फिर भी ऐसी आशंकाएँ लोकतांत्रिक अस्थिरता की ओर संकेत करती हैं। राज्यसभा चुनावों में बढ़ती क्रॉस वोटिंग ने समस्या को और जटिल बना दिया है।कभी यह दुर्लभ घटना मानी जाती थी,आज यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनती दिखाई देती है।हिमाचल प्रदेश,उत्तर प्रदेश,झारखंड, कर्नाटक और अन्य राज्यों में क्रॉस वोटिंग ने राजनीतिक दलों के भीतर अनुशासन और वैचारिक निष्ठा दोनों पर प्रश्न खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव में अलग रुख अपनाने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित तक करना पड़ा।सबसे बड़ी समस्या दल-बदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में दिखाई देती है।किसी विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है।अनेक मामलों में निर्णय लेने में महीनों और कभी-कभी वर्षों का समय लग जाता है। इस दौरान संबंधित जनप्रतिनिधि राजनीतिक लाभ उठाते रहते हैं।कई मामलों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि अध्यक्ष स्वयं किसी राजनीतिक दल से आते हैं, इसलिए निष्पक्षता को लेकर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लंबे समय से यह सुझाव दिया जा रहा है कि दल-बदल संबंधी मामलों का निर्णय किसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था अथवा निर्वाचन आयोग जैसी निष्पक्ष एजेंसी को सौंपा जाए। इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय हो सकती है।सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दल-बदल से लाभ किसे मिलता है? लोकतंत्र को नहीं,जनता को नहीं और विकास को भी नहीं।इसका सबसे बड़ा लाभ राजनीतिक दलों और सत्ता की राजनीति करने वाले नेताओं को मिलता है।जनता जिस विचारधारा के समर्थन में मतदान करती है,उसका प्रतिनिधि यदि बाद में दूसरी विचारधारा का झंडा उठा ले तो मतदाता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है।यही कारण है कि दल-बदल को अनेक राजनीतिक चिंतक "जनादेश की चोरी" तक कहने लगे हैं। विडंबना यह भी है कि लगभग सभी राजनीतिक दल इस विषय पर दोहरा आचरण अपनाते दिखाई देते हैं। जब उनके विधायक टूटते हैं तो लोकतंत्र खतरे में बताया जाता है, और जब दूसरे दलों के विधायक उनके पक्ष में आते हैं तो उसे जनसमर्थन की विजय कहा जाता है। यह दोहरा राजनीतिक चरित्र लोकतंत्र की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। यदि भारत को वास्तव में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होगा।राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और जनादेश का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। निवेश,प्रशासन, सुशासन और विकास की निरंतरता तभी संभव है जब राजनीतिक व्यवस्था स्थिर और विश्वसनीय हो। समय की मांग है कि दल-बदल विरोधी कानून को और प्रभावी बनाया जाए। यदि कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो उसकी सदस्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए।उसे पुनः जनता के बीच जाकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए।दल-बदल मामलों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।राज्यसभा चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए और राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने की व्यवस्था नहीं,बल्कि जनता के विश्वास की रक्षा का दायित्व भी है।यदि जनादेश बार- बार राजनीतिक अवसरवाद,सत्ता की गणित और जोड़-तोड़ का शिकार होता रहा तो लोकतंत्र की नैतिक शक्ति कमजोर होगी। वर्ष 2047 के विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब राजनीतिक दल अपने तात्कालिक स्वार्थों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देंगे।आज प्रश्न किसी एक दल का नहीं,बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता का है।यदि जनादेश सुरक्षित रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा।यदि जनादेश राजनीतिक अवसरवाद का बंधक बनता रहा तो लोकतंत्र का भविष्य निरंतर प्रश्नों के घेरे में बना रहेगा।विकसित भारत की यात्रा में यह केवल राजनीतिक नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है।

गौसेवा और समाजसेवा के पर्याय : गेयासी राम गुप्ता

लोकतंत्र की शान

भिवाड़ी। राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में यदि गौसेवा, समाजसेवा और जनकल्याण की बात की जाए तो श्री गेयासी राम गुप्ता का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वे केवल एक गौसेवक ही नहीं, बल्कि ऐसे समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा, संस्कार और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। भिवाड़ी निवासी गेयासी राम गुप्ता वर्षों से गौमाता की सेवा और संरक्षण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका मानना है कि गौसेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, करुणा और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। इसी भावना के साथ वे गौसंरक्षण से जुड़े अनेक अभियानों

में बढ़-चढ़कर भाग लेते रहे हैं तथा समाज में गौमाता के प्रति सम्मान और जागरूकता फैलाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। गौसेवा के साथ-साथ गेयासी राम गुप्ता सामाजिक गतिविधियों में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वे जरूरतमंद लोगों की सहायता, सामाजिक जागरूकता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता तथा समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में पिरोने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल सेवा करना ही नहीं, बल्कि समाज में भाईचारा, सहयोग और संस्कारों की भावना को मजबूत करना भी है। उनकी सादगी, मिलनसार व्यक्तित्व और निस्वार्थ सेवा भावना ने उन्हें भिवाड़ी ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। समाज के युवाओं के लिए वे प्रेरणास्रोत हैं और उन्हें समाज तथा राष्ट्रहित के कार्यों में आगे आने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हाल ही में गेयासी राम गुप्ता दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वप्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र "दैनिक लोकतंत्र की शान" को एक विशेष एवं प्रेरणादायक साक्षात्कार दिया। इस साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, गौसेवा के अनुभवों तथा देशभर से प्राप्त 180 से अधिक सम्मानों और पुरस्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उन्हें गौसेवा, समाजसेवा, जनकल्याण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सम्मान उनके लिए केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और अधिक बढ़ाने वाली प्रेरणा है। साक्षात्कार के दौरान गेयासी राम गुप्ता ने कहा कि सेवा का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन यदि व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करे, तो उसे लोगों का प्रेम और सम्मान स्वतः प्राप्त होता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जीवन का कुछ समय समाजसेवा, गौसंरक्षण और मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए अवश्य समर्पित करें। आज गेयासी राम गुप्ता अपने सेवा कार्यों, गौभक्ति और समाज के प्रति समर्पण के कारण हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बने हुए हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और समाज के लिए किया गया प्रत्येक कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। निस्संदेह, गेयासी राम गुप्ता का जीवन सेवा, संस्कार, समर्पण और राष्ट्रहित की भावना की एक ऐसी प्रेरक गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।

फिलिप्स का पहला शतक, मैकुलम-गप्टिल के क्लब में एंट्री

जो रूट के लिए बढ़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का इंतजार

नई दिल्ली। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 96.2 ओवर में 391 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स की बेहतरीन शतकीय पारी की बदौलत टीम इस स्कोर तक पहुंचा। फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया और अब वह इसी के साथ एक खास मामले में ब्रेंडन मैकुलम और मार्टिन गुप्टिल की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले मैकुलम और गुप्टिल ने ही यह कारनामा किया था।

जो रूट के लिए बढ़ा इंतजार

इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पारी की शुरुआत बहुत खास नहीं रही। 45 पर पहला विकेट गिरा और बेन डकेट 25 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद 68 रन पर दूसरा विकेट गिरा और जैकब बेथेल 9 रन ही बना पाए। इसके बाद दूसरे ओपनर एमिलियो गे 53 रन बनाकर डटे रहे और तीसरे विकेट के लिए जो रूट के साथ 74 रन की पार्टनरशिप की। जो रूट ने 57 गेंद पर 46 रन की पारी खेली। उन्हें इस पारी से पहले 14 हजार टेस्ट रन पूरे करने के लिए 48 रन चाहिए थे।

IPL 2027 की शुरुआत कब, BCCI ने दी जानकारी

अगले सीजन में खेले जाएंगे इतने मुकाबले

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 के शेड्यूल को पहले की तारीखों में शिफ्ट करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस योजना के तहत आईपीएल के अगले सीजन को लगभग 10 मार्च से शुरू करके 15 मई तक खत्म करने पर चर्चा चल रही है। इस तरह का विचार खिलाड़ियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए किया जा रहा है। बीसीसीआई के सचिन देवाजीत सैकिया ने पीटीआई से इस बात की पुष्टि की।

- **10 मार्च से हो सकती है अगले सीजन की शुरुआत–** आईपीएल के अगले सीजन को जल्दी शुरू करने का ये प्रस्ताव मई के आखिर में मौसम के हालात को लेकर बढ़ती चिंताओं और आईपीएल के दो महीने के समय के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट के व्यस्त कैलेंडर को फिट करने की चुनौती के बीच आया है। बीसीसीआई सचिव सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि इस साल यानी आईपीएल 2026 की शुरुआत 29 मार्च (या 28 मार्च) के आसपास शुरू हुआ और 31 मई को खत्म हुआ। हम बस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि टूर्नामेंट के आखिरी दिनों में यानी 15 मई के बाद बारिश होने या प्री–मानसून सीजन शुरू होने की आशंका रहती है। देवाजीत सैकिया ने आगे कहा कि दूसरी तरफ गर्मी का मौसम भी होता है, जो न तो खिलाड़ियों के लिए और न ही दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होता है। सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई की मुख्य चिंता खेल और मैच देखने के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करना है, खासकर उन इलाकों में जहां आईपीएल सीजन के दूसरे हिस्से में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है।

मनिका बत्रा को एशियन गेम्स 2026 के स्क्वाड में नहीं मिली जगह

वर्ल्ड रैंकिंग में 45वें नंबर की खिलाड़ी को मिल गई एंट्री

नई दिल्ली। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को इस साल होने वाले एशियन गेम्स के स्क्वाड में एंट्री नहीं मिल पाई है। गुरुवार (18 जून) को सामने आए स्क्वाड में मनिका का नाम नहीं होना काफी हैरानी भरा था। मनिका ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (ञ्ञ्ञस्त्रढ्ढ) द्वारा तय किए गए सेलेक्शन मानक में वह खरी नहीं उतर पाईं। वहीं उनकी जगह वर्ल्ड रैंकिंग में 45वें स्थान पर काबिज श्रीजा अकुला को महिला टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है। गौरतलब है कि मनिका बत्रा लंबे समय से घरेलू इवेंट्स से दूर रही हैं। यही कारण है कि उनकी नेशनल रैंकिंग पर असर पड़ा है। जबकि टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में मनिका श्रीजा से नीचे 51वें स्थान पर मौजूद हैं। जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों का 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजन होगा।

क्या है टेबल टेनिस टीम की चयन प्रक्रिया?

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने अपनी चयन प्रक्रिया के मानक के बारे में बताया, 'चयन प्रक्रिया के मुताबिक भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को उनके हालिया प्रदर्शन के हिसाब से स्क्वाड में जगह दी गई है।' एशियाई खेलों में टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं का आयोजन 20 सितंबर से 28 सितंबर तक होगा। 2023 में बनाई गईं सेलेक्शन पॉलिसी के मुताबिक 50 प्रतिशत वेटेज नेशनल रैंकिं, 40 प्रतिशत वर्ल्ड रैंकिंग और 10 प्रतिशत चयन समित के फैसलों के ऊपर निर्भर होता है।

'सचिन तेंदुलकर भगवान हैं, वैभव सूर्यवंशी ईश्वर का बेटा'

श्रीकांत ने 15 साल के बल्लेबाज को बताया जबरदस्त प्रतिभा

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के ही है और उनकी तुलना क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से होने लगी है। हालांकि, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने फैंस से अपील की है कि वे वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन तेंदुलकर से न करें। कृष्णामचारी श्रीकांत ने कहा कि सचिन, सचिन हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।

श्रीकांत ने कहा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं और वैभव सूर्यवंशी 'ईश्वर का बेटा' है। उन्होंने कहा कि वैभव को किसी से तुलना के दबाव में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से अपना खेल खेलने देना चाहिए। हालांकि, उन्होंने वैभव को जबरदस्त प्रतिभा बताते हुए कहा कि अगर उसे सही समय और समर्थन मिला तो वह भारत के लिए भविष्य का मैच विनर बन सकता है।

श्रीकांत ने युवा बल्लेबाज की तारीफ करते हुए कहा कि उसके शॉट्स, बैट स्पीड

और दबाव में खेलने की क्षमता उसे खास बनाती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने श्रीकांत के हवाले से लिखा, ''सचिन और वैभव सूर्यवंशी की तुलना न करें। बात यहीं खत्म करते हैं। सचिन क्रिकेट के भगवान हैं और मेरा मानना ??है कि यह लड़का, वैभव सूर्यवंशी, भगवान का बेटा है। इसे ऐसे ही रहने दें।''

'अलग दौर की तुलना में विश्वास नहीं'

श्रीकांत ने कहा, ''मैं अलग-अलग दौर की तुलना करने में विश्वास नहीं रखता, इसलिए सचिन की तुलना किसी से न करें। सचिन, सचिन हैं।

मनप्रीत सिंह 400 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें हॉकी खिलाड़ी बने

नई दिल्ली। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह के लिए 18 जून 2026 का दिन खास रहा। इस दिन भारत ने रॉटरडम में जहां एफआईएच हॉकी प्रो लीग के अपने दूसरे मैच में जर्मनी को 3-1 से हराया, वहीं मनप्रीत सिंह ने अपना 413वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर सबसे अधिक मैच खेलने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मनप्रीत सिंह से पहले यह रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप टिर्की के नाम था। दिलीप टिर्की ने भारत के लिए 412 मैच खेले थे। मनप्रीत सिंह 400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के आठवें हॉकी खिलाड़ी हैं।

व्यापार

आईटी शेयरों के लिए 'ब्लैक फ्राइडे', पूरा सेक्टर धड़ाम

नईदिल्ली, एजेंसी। शुक्रवार शेयरों के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो रहा है। घरेलू शेयर मार्केट में शुक्रवार को आईटी सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। एक्सेंचर के कमजोर आउटलुक और वैश्विक मांग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आज 1,636.20 अंक यानी 5.75 प्रतिशत टूटकर 26,830.25 पर आ गया। यह पिछले एक महीने में सेक्टर की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। आज आईटी दिग्गज इंफोसे में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। 8.16 प्रतिशत गिरकर 1,035.50 रुपये पर आ गया। खास बात यह रही कि कारोबार के दौरान यह 1,030 रुपये तक फिसल गया, जो इसका 52 सप्ताह का नया निचला स्तर है। पिछले 30 दिनों में शेयर 13.43 प्रतिशत टूट चुका है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का शेयर 6.02 प्रतिशत गिरकर 2,070.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कारोबार के दौरान यह 2,059.90 रुपये तक लुढ़क गया। वहीं एम्फेसिस में भी भारी बिकवाली रही और शेयर 6.06 प्रतिशत टूटकर 2,194.90 रुपये पर आ गया। आईटी सेक्टर की कमजोरी केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही। टेक महिंद्रा सुबह 10 बजे तक 5.28 प्रतिशत टूट चुका था। 4.98 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही थी। जबकि, एलटीआई माइंडट्री 4.58 प्रतिशत टूट चुका था। पर्सिस्टेंट सिस्टम भी 4.56 प्रतिशत नीचे था जबकि, विप्रो में 3.62 प्रतिशत गिरावट थी। कंसल्टिंग कंपनी ने अपने पूरे साल के राजस्व वृद्धि अनुमान को घटा दिया है। कंपनी ने चौथी तिमाही के लिए भी कमजोर आउटलुक दिया है।

इससे निवेशकों को डर है कि अमेरिका और यूरोप में आईटी खर्च में सुस्ती आ सकती है, जिसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है।

यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा इसी महीने से निकाल सकेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के 7 करोड़ से अधिक सदस्य यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से फंड निकाल सकेंगे। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि यह सुविधा इस महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज सदस्यों के खातों में इसी महीने भेज दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया तहत सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का काम पूरा हो चुका है। इस महीने के अंत तक जरिए फंड निकासी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।' उन्होंने कहा कि सदस्य अपने क्लेम की रकम के जरिए अपने बैंक खाते में तुरंत ले सकेंगे और फिर किसी भी निकाल सकेंगे। अधिकारी ने बताया, 'यह सुविधा शुरू करने से पहले आने वाले दिनों में सर्वर कम से कम 3 दिनों के लिए ब्लैकआउट कर जाएंगे। शुरू होने वाली व्यवस्था को अपडेट करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। नियमों के मुताबिक, मेंबर के अकाउंट में अंशदान का 25 प्रतिशत हिस्सा मिनिमम बैलेंस के रूप में रहना अनिवार्य है। वहीं, बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर बनाने जैसे मामलों में 5 लाख रुपये तक के क्लेम का ऑटो–सेटलमेंट होता है।

स्विस बैंकों का टूटा तिलिस्म

2025 में 8 प्रतिशत की आई गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। स्विस बैंकों में जमा भारतीय पैसा साल 2025 में आठ फीसदी से ज्यादा घटा है। यह घटकर 3.25 अरब स्विस फ्रैंक (करीब 36,793 करोड़ रुपये) रह गया। स्थानीय शाखाओं के साथ अन्य बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के जरिये रखी गई रकम में कमी के कारण यह गिरावट हुई। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) की तरफ से गुरुवार को जारी वार्षिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इन आंकड़ों के मुताबिक, कुल जमा राशि में गिरावट आने के बावजूद व्यक्तिगत और संस्थागत ग्राहकों के खातों में जमा धन 50 फीसदी से अधिक बढ़कर 52.4 करोड़ स्विस फ्रैंक (करीब 6,000 करोड़ रुपये) हो गया। हालांकि, कुल राशि में इन जमाओं की हिस्सेदारी लगभग 16 फीसदी ही रही।

क्या है इसका मतलबः अब स्विट्जरलैंड भारतीय टैक्स चोरों और बड़े व्यवसायियों के लिए 'सेफ हेवन' नहीं रह गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लागू 'सूचनाओं का ऑटोमैटिक आदान-प्रदान' है। इसके तहत स्विस बैंक हर साल भारतीयों के खातों की पूरी वित्तीय जानकारी सीधे भारत सरकार को सौंप देते हैं। इस पारदर्शिता और भारत सरकार की सख्त टैक्स नीतियों के डर से लोग स्विस बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि, इस गिरावट के बीच व्यक्तिगत बचत खातों में पैसों का बढ़ना यह दिखाता है कि जो लोग नियमों का पालन कर

रहे हैं, वे अभी भी कानूनी और घोषित रूप से वहां निवेश कर रहे हैं।

एसएनबी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 के अंत में मौजूद कुल 325.05 करोड़ स्विस फ्रैंक की देनदारियों में से 52.4 करोड़ स्विस फ्रैंक ग्राहक जमा, 2.6 अरब स्विस फ्रैंक अन्य बैंकों के जरिये, 1.86 करोड़ स्विस फ्रैंक विश्वस्त संस्था या ट्रस्ट के जरिये और 10.57 करोड़ स्विस फ्रैंक बॉन्ड और प्रतिभूतियों जैसे अन्य वित्तीय साधनों के रूप में थे।

एसएनबी के आंकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीयों की कुल जमा राशि साल 2006 में करीब 6.5 अरब स्विस फ्रैंक के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें ज्यादातर समय गिरावट का रुख रहा। हालांकि, 2011, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 जैसे कुछ सालों में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। एसएनबी ने साफ किया कि ये आंकड़े बैंकों की ओर से रिपोर्ट की गई कुल देनदारियों को दिखाते हैं। इन्हें स्विस बैंकों में काले धन का प्रत्यक्ष संकेतक नहीं माना जा सकता।

कुल रकम में यह रहा बड़ा हिस्सा

कुल धनराशि का बड़ा हिस्सा 'बैंकों को देय राशि' के रूप में रहा, जो अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिये रखी गई थी। यह राशि पिछले साल करीब 15 फीसदी घटकर 2.6 अरब स्विस फ्रैंक रही। इससे पहले वर्ष 2024 में स्विस बैंकों में जमा कुल भारतीय धन तिगुना होकर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया था, जो 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। साल 2021 में यह आंकड़ा 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पर था। ये बैंकों की तरफ से स्विस नेशनल बैंक को दी गई सूचनाओं पर आधारित आंकड़े हैं। स्विट्जरलैंड में भारतीयों के पास मौजूद काले धन की बहुचर्चित मात्रा को नहीं ये दिखाते हैं। इन आंकड़ों में वह धन भी शामिल नहीं होता जो भारतीयों, प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) या अन्य लोगों की ओर से स्विस बैंकों में तीसरे देशों की इकाइयों के नाम पर रखा गया है।

8,000 करोड़ के शेयर लेकर बैठे हैं राधाकृष्ण दमानी, 1 भी शेयर नहीं बेचेंगे

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत के सबसे बड़े आईपीओ बनने जा रहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 30,000 करोड़ रुपये के पब्लिक इश्यू में जहां सरकारी बीमा कंपनियां और कई विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाने की तैयारी में हैं, वहीं देश के कुछ दिग्गज निवेशकों ने एक भी शेयर बेचने का फैसला नहीं किया है। सबसे बड़ा नाम डीमार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी का है। दमानी के पास एनएसई के 3.90 करोड़ से अधिक शेयर हैं, जो कंपनी में 1.58 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं। अनलिस्टेड मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 2,055 रुपये प्रति शेयर के आधार पर उनकी हिस्सेदारी की कीमत करीब 8,032 करोड़ रुपये बैठती है। इसके बावजूद उन्होंने एक भी शेयर बेचने का फैसला नहीं किया है। सनिल कांत मुंजाल और क्रिस गोपालकृष्णन भी होल्ड पर हीरो ग्रुप के संस्थापक सनिल कांत मुंजाल के पास एनएसई के 1.02 करोड़ शेयर हैं, जिनकी अनुमानित कीमत

2,040 करोड़ रुपये है। वहीं इंफोसिस के सह–संस्थापक एस. गोपालकृष्णन के पास 94.29 लाख शेयर हैं, जिनका मूल्य करीब 1,886 करोड़ रुपये आंका गया है। डीमार्ट के सीईओ इग्नेशियस नविल नरोन्हा के पास भी 30 लाख शेयर हैं, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये है। प्रसिद्ध निवेशक डॉली खन्ना के पास एनएसई के 15.16 लाख शेयर हैं, जिनकी कीमत करीब 311 करोड़ रुपये है। वहीं दिग्गज वैल्यू निवेशक रामदेव अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल के पास 8–8 लाख शेयर हैं, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 164 करोड़ रुपये प्रति निवेशक है।

इन्फोसिस 5 साल और टीसीएस 6 साल के लो पर

नई दिल्ली, एजेंसी। एशियाई बाजारों में तेजी के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई। इसकी सबसे बड़ी वजह आईटी शेयरों में आई गिरावट रही। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का शेयर 7 प्रतिशत लुढ़ककर छह साल के लो के करीब पहुंच गया। इसी तरह इन्फोसिस का शेयर भी 9 प्रतिशत गिरावट के

साथ 5 साल के लो पर आ गया। इसी तरह विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी गिरावट रही। अनुमान की ऊपरी सीमा घटाने के बाद टेक्नोलॉजी पर होने वाले खर्च में कटौती कमजोरी को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। इसका असर आज आईटी शेयरों में देखने को मिला। टीसीएस का शेयर बीएसई पर करीब 7 फीसदी गिरावट के साथ 2,060.50 रुपये तक लुढ़क गया जो इसका 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर है। शेयरों में भारी गिरावट, इन्फोसिस और टीसीएस 52 हफ्ते के लो पर रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान घटाने से मचा गया यह हाहाकार निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 6 प्रतिशत गिरावट, इन्फोसिस 8 प्रतिशत लुढ़का यह बिकवाली के शेयरों में 11 प्रतिशत की गिरावट के बाद हुई कमजोर आउटलुक इस बात का संकेत है कि कंपनियां आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पर अपनी खर्च में कटौती कर सकती हैं। इस घटनाक्रम पर भारतीय आईटी कंपनियों की बारीकी नजर हैं क्योंकि वे अपना बड़ा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से कमाती हैं। यही वजह है कि उनके शेयरों में गिरावट आई है।

रातोंरात अरबपति बन गए ये नौजवान

बॉर्डर पार हुई दोस्ती और अब 5 लाख करोड़ जेब में आए

नई दिल्ली, एजेंसी। दो युवा एंटरप्रेन्योर रातोंरात अरबति बन गए हैं। इनमें से एक भारतीय है। दूसरा पाकिस्तानी। ऐसा एलन मस्क की बदौलत हुआ है। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने लोकप्रिय कोडिंग असिस्टेंट 'कर्सर' बनाने वाली कंपनी 'एनीस्फीयर' का 60 अरब डॉलर (करीब 5 लाख करोड़ रुपये) में सौदा किया है। इसके चलते अमन सांगर और सुलेह आसिफ अरबपति की लिस्ट में शुमार हो गए हैं।

भारत में जन्मे 25 साल के अमन सांगर और पाकिस्तान के 26 साल के सुलेह आसिफ को इस डील से लगभग 2.7 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। इससे वे दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। डेवलपमेंट को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। रॉयटर्स के साथ पहले शेयर किए गए कंपनी के डेटा के अनुसार, कर्सर ने अपने कामकाज का तेजी से विस्तार किया है। लगभग 2.6 अरब डॉलर का सालाना एंटरप्राइज रेवेन्यू हासिल किया है। एआई स्टार्टअप बनाने के लिए अपने भविष्य के को-फाउंडर्स के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने अपना खुद का एआई कंसल्टिंग बिजनेस भी शुरू किया था।

सुलेह आसिफ कौन हैं – मूल रूप से पाकिस्तान के कराची के रहने वाले सुलेह आसिफ का गणित और कंप्यूटर साइंस में मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है। फोर्ब्स के अनुसार, उन्होंने 2016 से 2018 तक इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया।

2022 में एमआईटी में हुई थी शुरुआत

अमन सांगर ने 2022 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अपने दोस्तों के साथ मिलकर 'कर्सर' की शुरुआत की थी। इन दोस्तों में माइकल ट्रूएल, सुलेह आसिफ और अरविड लुनमार्क शामिल थे। जो कभी एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब सिलिकॉन वैली की सबसे तेजी से बढ़ने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक बन गया है। कर्सर के पावर्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब दुनिया भर की लगभग 50,000 कंपनियों में लाखों डेवलपर्स करते हैं। इनमें एनवीडिया, एडोब, शॉपिफाई और पेपॉल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि उसने 1 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू पार कर लिया है। इससे यह सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों में से एक बन गई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)